CMYK

केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा ने मचाया कहर, प्रदेश में एक और युवक की मौत; अब तक सात की जा चुकी है जान

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

गुजरात के पावागढ़ मंदिर में भीषण हादसा, रोपवे का तार टूटने से 6 की मौत

RNI Regn. No.7789/1964 वर्ष-61 > अंक - 253 रायपुर रविवार 07 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक

बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी

नई दिल्ली

बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर मचे बघमासां के बीच भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) अब इसे पूरे देश में कराने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की एक बैठक बुलाई है।

बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के अलावा सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बिहार में चलाया गया एसआईआर अभियान एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं।

चूंकि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक जंग फिर से छिड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एसआईआर अभियान का विरोध किया है, जबकि भाजपा शासित राज्यों ने चुनाव आयोग का समर्थन किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले महीने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में एसआईआर को लेकर आयोग पर लगे पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग भ्रम फैलाकर और चुनाव निकाय तथा मतदाताओं, दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर मतदाताओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा

मोदी यूएन जनरल डिबेट में नहीं होंगे शामिल
विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र की हाई-लेवल जनरल डिबेट में शामिल नहीं होंगे। जारी संशोधित अस्थायी सूची के अनुसार, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर 27 सितंबर को विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। पहले की सूची में कहा गया था कि पीएम मोदी 26 सितंबर को भाषण देंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा, जबकि हाई-लेवल जनरल डिबेट 23 से 29 सितंबर तक चलेगी।

23 सितंबर को होना है ट्रंप का संबोधन - इस सेशन में ब्राजील की तरफ से परंपरागत रूप से पहला भाषण होगा, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को UNGA के मंच से अपनी बात रखेंगे। यह ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद UNGA में पहला भाषण होगा। 26 सितंबर को इजरायल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शीर्ष नेता जनरल डिबेट में बोलेंगे। इस साल का सत्र खास है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। सत्र का थीम है- 'बेटर टुगेदरः 80 इयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स'।

सत्र के दौरान होंगी कई अहम बैठकें - बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सितंबर का महीना हर साल सबसे व्यस्त समय होता है। इस बार सत्र के दौरान कई अहम बैठकें होंगी। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष बैठक होगी। इसके अलावा, 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एक जलवायु शिखर सम्मेलन (क्लाइमेट समिट) की मेजबानी करेंगे, जहां विश्व नेता अपने नए राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को पेश करेंगे। इस साल बीजिंग में 1995 में हुई चौथी विश्व महिला सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। इसके अलावा भी इस सत्र में कई और महत्वपूर्ण बैठकें होंगी।

भारत और अमेरिका मे जारी है व्यापारिक तनाव - बता दें कि इस साल फरवरी में पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत तक के टैरिफ लगाए हैं, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है। यह UNGA सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब इजरायल-हमास युद्ध और यूक्रेन संकट जैसे वैश्विक मुद्दे चर्चा में हैं। बता दें कि UNGA की अस्थायी सूची में बदलाव की संभावना हमेशा रहती है। जैसे-जैसे हाई-लेवल सप्ताह नजदीक आएगा, वक्ताओं और शेड्यूल में और बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर इस मंच पर देश का पक्ष मजबूती से रखेंगे।

मुंबई में धमाकों की धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार, 34 मानव बम लगाने का किया था दावा

नोएडा एजेंसी

मुंबई में बम धमाकों की गंभीर धमकी देने के मामले में उत्तर प्रदेश के नोएडा से अश्विन कुमार सुप्रा (50) नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने उसे मुंबई लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हाल ही में उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा संदेश मिला था। इसमें दावा किया गया था कि शहर में 34 वाहनों में 34 मानव बम लगाए गए हैं। धमकी में कहा गया कि इन बमों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और विस्फोट से पूरी मुंबई दहल जाएगी। इस संदेश में खुद को ÷लश्कर-ए-जिहादी÷ नामक आतंकी संगठन से जोड़ने का भी दावा किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर में 40 साल बाद ऐतिहासिक फैसला, पुजारियों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा

वाराणसी एजेंसी।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों, अर्चकों और कर्मचारियों के लिए 40 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। गुरुवार को हुई श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 108वीं बैठक में ऐतिहासिक कर्मचारी सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दी गई। इस फैसले के बाद मंदिर के सभी कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा, जिससे उनके वेतन में लगभग तीन गुना की भारी बढ़ोतरी होगी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में करीब दो दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसने मंदिर के विकास और व्यवस्था की नई रूपरेखा तैयार कर दी है। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने बताया, अभी तक पुजारियों को लगभग 30 हजार रुपये मासिक मिलते थे, जो अब बढ़कर 80 से 90 हजार रुपये हो जाएगा।÷

बस चालकों की हर तीन महीने में मेडिकल और फिटनेस जांच अनिवार्य हो : सीएम योगी

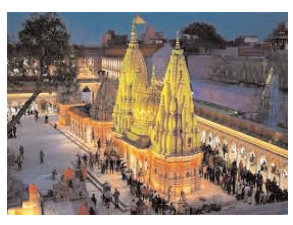

लखनऊ संवाददाता।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर तीन माह में बस चालकों की मेडिकल और फिटनेस जांच अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जनसुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ और डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बस चालकों का नियमित मेडिकल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट हर तीन महीने में अनिवार्य रूप से कराया जाए। विशेष रूप से आंखों की जांच जरूरी है ताकि दृष्टि दोष के कारण दुर्घटनाएं न हों।

उन्होंने कहा कि सड़क पर अंदाजे से गाड़ी चलाने की छूट नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास देश में सबसे बड़ा बेड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं देना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उन्होंने रक्षाबंधन पर बहनों को तीन दिनों तक मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराने की पहल को सराहनीय बताया और कहा कि विभाग भविष्य में इस तरह की सेवाओं का प्रचार-प्रसार और प्रभावी तरीके से करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र यदि समय की गति से पीछे जाता है तो हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। लेकिन यदि वह समय की गति से दो कदम आगे चलने की क्षमता रखता है, तो विजयश्री का ध्वज फहराता है। उन्होंने परिवहन विभाग से अल्पकालिक (3 वर्ष), मध्यम अवधि (10 वर्ष) और दीर्घकालिक (22 वर्ष) योजनाएं तैयार करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि परिवहन विभाग ने समय-समय पर अपनी सेवाओं से मिसाल पेश की है। 2019 के प्रयागराज कुंभ और 2020 की वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब करोड़ों कामगार और श्रमिक अपने-अपने राज्यों और गांवों की ओर लौट रहे थे, तब विभाग ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड तक प्रवासियों को सुरक्षित पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसी वर्ष आयोजित प्रयागराज महाकुंभ में भी विभाग ने रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों पर उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करते हुए करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से उनके गंतव्य तक पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संकट की घड़ी में परिवहन विभाग ने समय का सच्चा साथी बनकर प्रदेश और समाज की सेवा की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रदेश के लिए एक गंभीर चुनौती है।

161 यात्रियों की अटकीं सांसें, हवा में बंद हुआ एयर इंडिया विमान का इंजन

इंदौर ,एजेंसी इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया और यात्रियों की धड़कनें थम गईं, जब दिल्ली से आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान का इंजन हवा में ही बंद हो गया। पायलट की एक इमरजेंसी कॉल ने एयरपोर्ट पर खलबली मचा दी, जिसके बाद विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में कुल 161 लोग सवार थे, जिनकी जान कुछ पलों के लिए हलक में अटकी रही। यह घटना एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या AXB 1028 के साथ हुई। विमान दिल्ली से इंदौर के लिए अपनी नियमित उड़ान पर था और लैंडिंग के लिए इंदौर के आसमान में पहुंच चुका था। तभी अचानक पायलट को विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी का पता चला और कुछ ही देर में इंजन ने काम करना बंद कर दिया।

हैदराबाद में 69 फीट ऊंचे 'विश्व शांति महाशक्ति गणपति' ने खींचा सबका ध्यान

विश्व

फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में आएंगे मैंक्रो

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की, परस्पर साझेदारी बढ़ाने पर जोर

दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हाल के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया

एजेंसी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आर्थिक, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक आकलन किया। दोनों नेताओं ने होराइजन 2047 रोडमैप, हिंद-प्रशांत रोडमैप और रक्षा औद्योगिक रोडमैप के अनुरूप भारत- फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया।

दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में हाल के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया और भारत में राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करने के प्रति उत्सुकता व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु परस्पर संपर्क में बने रहने तथा साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।

नरम पड़े ट्रंप के तेवर : नरेंद्र मोदी को बताया 'महान प्रधानमंत्री'

पीएम ने भी दिया जवाब

वाशिंगटन ,06 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रशंसा किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'महान प्रधानमंत्री' कहा। इस पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं और उनके संबंधों के 'सकारात्मक आकलन' की गहराई से सराहना करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक व वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आए। भारत-अमेरिका के बीच संबंधों को 'बेहद खास' बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वे एक महान प्रधानमंत्री हैं। मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे इस समय वे जो कर रहे हैं, वह पसंद नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद खास रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी-कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं।

इस दौरान, डोनाल्ड ट्रंप भारत को चीन के हाथों 'खोने' संबंधी अपनी टिप्पणी से पीछे हटते दिखाई दिए। ट्रंप से उनके बयान के बारे में पूछा गया, क्या उन्होंने भारत को चीन के हाथों खो देने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है? जवाब में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को जिम्मेदार ठहराया है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया, क्योंकि अमेरिका ने भारत के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था, और फिर रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क जोड़ा। भारत ने जवाब में अमेरिका के इस कदम को 'अनुचित' बताया।

ट्रंप का बड़ा ऐलान, सर्राफा समेत इन सामानों से हटाया टैरिफ

वाशिंगटन ,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कुछ बदलाव किए है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने 2 अप्रैल को लागू किए गए अपने रेसिप्रोकल टैरिफ में चेंज करते हुए कुछ वस्तुओं जिनमें सर्राफा से संबंधित वस्तुएं और कुछ महत्वपूर्ण खनिज एवं दवा उत्पाद शामिल हैं को टैरिफ से बाहर कर दिया है। नए आदेश में एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, रेजिन और सिलिकॉन उत्पाद भी शामिल हैं, जिन पर पारस्परिक शुल्क लागू होंगे। शुक्रवार को जारी एक कार्यकारी आदेश में यह बदलाव किया गया है। ये बदलाव सोमवार से लागू होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास आदेश जारी किया, जिसमें ग्रेफाइट, टंगस्टन, यूरेनियम, सोने के बुलियन और कई दूसरी धातुओं पर देश-आधारित टैरिफ हटा दिया गया।

भारत पर टैरिफ हटाने ट्रंप के मंत्री ने रखी 3 शर्तें

भारत ने दिया ये जवाब

वाशिंगटन ,06 सितंबर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को चीन के हाथों खोने संबंधी अपनी पिछली टिप्पणी से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका के उद्योग मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत पर 25त्न एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने के लिए तीन शर्त रखीं।

एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, [illegible] से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप (भारत) रूस और चीन के बीच ब्रिज बनना चाहते हैं तो बने, लेकिन या तो डॉलर का या अमेरिका का समर्थन करें। अपने सबसे बड़े ग्राहक का सपोर्ट करें या 50त्न टैरिफ चुकाएं। हालांकि, उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा बातचीत के लिए तैयार है।

इसके साथ ही लुटनिक ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव है, लेकिन जल्द ही भारत माफी मांगकर राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ बातचीत की टेबल पर आएगा। उन्होंने कहा कि एक-दो महीने में भारत ट्रम्प के साथ बातचीत की टेबल पर आएगा और माफी मांगेगा। लुटनिक के मुताबिक, भारत ट्रम्प के साथ नया सौदा करने की कोशिश करेगा। यह सौदा ट्रम्प की शर्तों पर होगा और वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसे अंतिम रूप देंगे।

वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार के मुद्दों पर बातचीत जारी रखेगा। उन्होंने कहा- हम क्वाड को चार देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अच्छा मंच मानते हैं।

CMYK

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

कच्चापाल जलप्रपात बनेगा पर्यटन का केंद्र

पर्यटन केन्द्र बनने से क्षेत्र के स्व-सहायता समूह के महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार

रायपुर। पर्यटन केन्द्र बनने से क्षेत्र के स्व-सहायता समूह के महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान बाईक एवं पैदल चलकर कच्चापाल के जलप्रपात पहुंचकर अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ के जंगल, पहाड़ और झरने यहां की पहचान हैं। यदि इन्हें सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाए तो नारायणपुर जिले का नाम पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक रोशन होगा। कच्चापाल जलप्रपात को हम प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में कार्य करेंगे।

अबूझमाड़ की गोद में बसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कच्चापाल जलप्रपात अब जिले के पर्यटन मानचित्र पर नया आकर्षण का केन्द्र बनने जा रहा है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री ने यहां पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कच्चापाल वाटरफॉल का मनोहारी दृश्य, पहाड़, नदी-नाले और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्थानीय ग्रामसभा को शामिल करते हुए पर्यटन विकास की ठोस रूपरेखा तैयार की जाए। साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार की पहल की जाए, जिससे विशेषकर महिलाओं को आजीविका का नया अवसर मिल सकें।

विवेकान्द आश्रम कच्चापाल में पहुंचकर वन मंत्री ने शिक्षक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों के द्वारा संगीतमय स्वागत गीत के साथ वन मंत्री श्री कश्यप का स्वागत किया गया। इस अवसर उन्होंने बच्चों से कहा की अपने प्रथम गुरू माता-पिता के बताए रास्ते पर चलकर अपने भविष्य को गढ़ने का कार्य करें, जिससे भविष्य में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। गुरूजन मोमबत्ती के समान होते है जो जल कर दुसरे को प्रकाश देते है। इस प्रकार गुरूजनों से विद्यार्जन ग्रहण कर अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। गुरूजनों की मांग पर वादयंत्र एवं माईक सेट प्रदाय करने का घोषणा किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, एसडीएम अभयजीत मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन मौजूद थे।

सोनपुर में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखा का लोकार्पण

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के ग्राम सोनपुर में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।ग्रामीणों ने वन मंत्री से मिनी राइस मिल, सामाजिक भवन, खेल मैदान, किचन शेड और दंतेश्वरी मंदिर के पास शेड निर्माण जैसी मांगें रखी गईं। मंत्री श्री कश्यप ने इन सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण बैंक की नई शाखा के खुलने से सोनपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, जिला पंचायज हीना नाग सहित जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

ग्रामोद्योग से गाँव–गाँव में रोजगार का होगा विस्तार : मंत्री श्री गजेंद्र यादव

कारीगरों को मिलेगा नया बाजार, प्रदेश में बनेगा शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी

ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक : छोटे उद्योगों से बड़े रोजगार की ओर कदम

रायपुर। ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा एवं विधि विधायी विभाग के मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस रायपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभाग के अंतर्गत रेशम, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प एवं माटीकला बोर्ड की कार्यप्रगति का विस्तार से आकलन किया गया।

मंत्री श्री यादव ने बताया कि राज्य में लगभग 3.15 लाख हितग्राही ग्रामोद्योग के विभिन्न कुटीर उद्योगों से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों और विकासखंडों में रीपा (ऋद्धक्र) भवनों में ग्रामोद्योग की गतिविधियाँ संचालित कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनाङ्कपत्तल, कांसा, गोबर से जैविक खाद, पपीता से गुलकंद, फर्नीचर जैसे छोटे उद्योगों की स्थापना कर हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इसके अलावा राज्य शासन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शासकीय विभागों में केवल राज्य के बुनकरों और कारीगरों द्वारा निर्मित सामग्री की ही आपूर्ति हो। साथ ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में शिल्प ग्राम एवं शिल्प नगरी के निर्माण की कार्ययोजना बनाई जाएगी, ताकि कारीगरों को बेहतर विपणन सुविधा मिले और राज्य की शिल्पकला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। बैठक में सचिव सह संचालक ग्रामोद्योग श्री श्याम धावड़े, प्रबंध संचालक हस्तशिल्प एवं माटीकला बोर्ड श्री जे. पी. मौर्य, उप सचिव श्री अर्न मरकाम, अपर संचालक रेशम डॉ. राजेश बघेल, संयुक्त संचालक हथकरघा श्री अ. अयाज़ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, उफनती नदियों और टूटी पुलिया पर हाईकोर्ट सख्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, विशेषकर दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में है। इन क्षेत्रों में छात्र-छात्राएं टूटी हुई पुलिया और उफनती नदियाँ पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। बच्चों की इस दयनीय स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खुद पहल करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला बच्चों की जान और शिक्षा से जुड़ा है और ऐसी स्थिति को लंबे समय तक नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए पूरी स्थिति पर विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

यह मामला तब उजागर हुआ जब मीडिया रिपोर्ट्स में बच्चों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिनमें वे जान जोखिम में डालकर पानी भरी नदियाँ पार करते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे को स्वतः संज्ञान में लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि प्रभावित क्षेत्र में स्थायी पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। पहले तकनीकी जांच में 12 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद कांकेर कलेक्टर ने जवाब भेजकर प्रस्ताव में जरूरी संशोधन किए। यह संशोधित डीपीआर 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

स्कैम से बचने सड़क परिवहन विभाग के चालान के भुगतान के लिए वेबसाईट का ही उपयोग करना है

धोखे से बचने फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करना

अजनबी को आन लाइन पेमेंट बिल्कुल नहीं करना

जगदलपुर। सड़क परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों कोअपने चालान की जांच करने के लिए अधिकारिक विभागीय वेबसाईट पर जाकर ई-चालान के पेज पर जानकारी प्राप्त कर भुगतान करने की कार्यवाही करने अपील की गई है। जहाल के दिनों में छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क परिवहन विभाग ने ई-चालान से संबंधित स्कैम सामने आ रहे है। जिसमें नकली ई-चालान के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने के बारे में छदम तरीके से डराने वाले संदेश-मैसेज के माध्यम से लिंक भेजकर आम लोगों की व्यक्तिगत जानकारी और जमा खाते से पैसे चुरा लेने की घटना हुई है। परिवहन विभाग द्वारा आम लोगों से यह अपील है कि ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए मैसेज या लिंक पर क्लिक न करें। अपने वास्तविक चालान की जांच करने के लिए अधिकारिक विभागीय पर जाकर ई-चालान के पेज पर पे ऑनलाइन पर क्लिक कर चालान नंबर एवं कैप्चा कोड डालकर गेट डिटेल पर क्लिक कर मोबाईल ओटीपी डालकर चालान विवरण संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुलिस एवं परिवहन के प्रवर्तन अमले द्वारा जब भी ई-चालान किया जाता है। पंजीकृत मोबाईल में संबंधित को टेक्स्ट मैसेज अधिकारिक के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। आम लोगों की जागरूकता के लिए यह अपील है कि यदि आपको किसी ई-चालान मैसेज के साथ कोई लिंक मिलता है, तो उस पर कभी क्लिक न करें। कभी भी किसी अजनबी को ऑनलाईन पैसे का भुगतान न करें, और अपने खाते से किसी भी लेने देन से सावधान रहें। किसी भी धोखेबाज कॉल, संदेश या ऐप के संबंध में निकट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। आम लोगों की जागरूकता के लिए यह अपील है कि यदि आपको किसी ई-चालान मैसेज के साथ कोई लिंक मिलता है, तो उस पर कभी क्लिक न करें। कभी भी किसी अजनबी को ऑनलाईन पैसे का भुगतान न करें, और अपने खाते से किसी भी लेने देन से सावधान रहें।

तिल्दा शराब दुकान पर विवाद : उड़नदस्ता अधिकारी पर मारपीट और अवैध वसूली का आरोप

रायपुर । तिल्दा स्थित एक सरकारी शराब दुकान में ओवररेट शराब बिक्री के आरोपों की जांच करने पहुंचे आबकारी विभाग के संभागीय उड़नदस्ता अधिकारी उत्तम भारद्वाज खुद ही विवादों में घिर गए हैं। दुकान के कर्मचारियों ने अधिकारी पर न सिर्फ मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है, बल्कि 60 हजार रुपये की मांग करने और अंत में 25 हजार रुपये लेकर जाने की भी बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 2 सितंबर की बताई जा रही है, जब अधिकारी उत्तम भारद्वाज अचानक दुकान पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों पर शराब महंगे दामों में बेचने का आरोप लगाया और 60 हजार रुपये की मांग की। सुपरवाइजर मधु राय ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि दुकान में केवल निर्धारित दरों पर ही शराब बेची जा रही है और कोई अवैध वसूली नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि अधिकारी को यह जवाब नागवार गुज़रा और उन्होंने सुपरवाइजर के साथ बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उत्तम भारद्वाज ने गुस्से में आकर मधु राय को थप्पड़ मार दिया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दुकान के कर्मचारियों ने विरोध भी किया, लेकिन अंततः अधिकारी कथित रूप से 25 हजार रुपये लेकर चले गए।इस घटना को लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और उन्होंने इसकी लिखित शिकायत आबकारी विभाग में दर्ज कराई है। अब पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। अधिकारी द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो भी सामने आ चुका है, जो मामले को और गंभीर बना रहा है।

तालाब में डूबने से सीएसवीटी के उप कुलसचिव की मौत

दुर्ग। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालयसीएसवीटीयू भिलाई के उप कुलसचिव (उप-रजिस्ट्रार) डॉ. भास्कर चंद्राकर की तालाब में डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वे ग्राम पतोरा में एक तालाब से कमल का फूल तोड़ने के लिए पानी में उतरे थे। कमल की जड़ों और दलदली जमीन में फंसने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। यह घटना 4 सितंबर की शाम करीब 5 बजे की है। कार्यालयीन समय के बाद डॉ. चंद्राकर, मुख्य वित्त अधिकारी (ष्टस्नह्र) के साथ उतई क्षेत्र में स्थित अपने प्लॉट को देखने गए थे। लौटते समय ग्राम पतोरा में तालाब देखकर वे कमल का फूल तोड़ने तालाब में उतर गए। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और दलदल में फंसने से वे डूबने लगे।सहकर्मी ने तत्काल ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार सीपीआर देने के बाद पास के निजी अस्पताल ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें भिलाई स्थित बीएसपी सेक्टर-9 अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।डॉ. चंद्राकर मूल रूप से रायपुर के पचपेड़ी नाका, नवजीवन कॉलोनी के निवासी थे। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे रायपुर में किया जाएगा। घटना के बाद विश्वविद्यालय और शैक्षणिक जगत में शोक की लहर है। सीएसवीटीयू के कुलपति डॉ. अरुण अरोरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. चंद्राकर का असमय निधन तकनीकी शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वे एक सरल, मिलनसार और कुशल प्रशासक थे। डॉ. चंद्राकर ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से लेकर सीएसवीटीयू भिलाई और अन्य संस्थानों में लगभग 15 वर्षों तक सेवा दी।

डोंगरगढ़ में फर्जी राशन कार्ड रैकेट का भंडाफोड़, जनपद अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

डोंगरगढ़। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में फर्जी राशन कार्ड बनाने के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि वरिष्ठ जनपद पदाधिकारियों और सदस्यों के संरक्षण में कुछ ऑनलाइन सेंटर संचालक ग्रामीणों से तीन से पांच हजार रुपये वसूल कर अवैध तरीके से राशन कार्ड बना रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

ग्राम मेंढ़ा के एक ग्रामीण के पास से जब एक नया राशन कार्ड मिला, जिस पर पूर्व जनपद सीईओ सातपुते के डिजिटल हस्ताक्षर थे, तो शक की सुई इस पूरे सिस्टम पर उठी। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि एक सुनियोजित घोटाला है। जनपद पंचायत की सीईओ भगवती साहू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राशन कार्ड प्रभारी माखन चंद्रवंशी को जांच के निर्देश दिए। पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन सेंटर संचालक सैकड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बना चुके हैं, जिसके लिए ग्रामीणों से मोटी रकम वसूली गई है। प्रभारी माखन चंद्रवंशी ने स्वीकार किया कि फर्जीवाड़े के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं और अब पूरे विकासखंड में सभी सक्रिय राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा। सीईओ भगवती साहू ने भी कहा कि ऑनलाइन सेंटरों की भूमिका की जांच जारी है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घोटाले पर पूर्व जनपद अध्यक्ष भावेश सिंह और पूर्व जनपद सदस्य रवि अग्रवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस पूरे मामले को जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में लाते हुए दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, यह भी कहा गया कि भविष्य में राशन कार्ड निःशुल्क बनाए जाएं और गरीबों से अवैध वसूली पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।

बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान तेज

नारायणपुर । बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिलने की खबर है। सूत्रों के अनुसार, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर चल रही मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को नक्सलियों की एक गुप्त बैठक और उनके जुटान की सूचना मिली थी।

सरल और सहज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिखा अपनत्व, नन्हे इवान को गोद में लेकर किया दुलार

नन्हे इवान को गोद में लेकर किया दुलार

रायपुर। रायगढ़ के खरसिया पहुँचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सहजता, सरलता और अपनेपन ने आज सभी को गहरे तक प्रभावित किया। खरसिया हेलीपैड पर जब उनकी नज़र ढाई साल के इवान पर पड़ी तो वे बच्चे को दुलारे बिना नहीं रह सके। आत्मीय मुस्कान के साथ मुख्यमंत्री श्री साय ने नन्हे इवान को अपनी गोद में उठाया और बड़े स्नेह से दुलार किया। नर्सरी में पढ़ने वाला इवान अपने पिता के साथ बड़े उत्साह से हेलीपैड पर मुख्यमंत्री को देखने आया था। बच्चे को अचानक मुख्यमंत्री श्री साय की गोद में देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक और आश्चर्यचकित रह गए। यह दृश्य मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सहजता, आत्मीयता और संवेदनशील व्यवहार का सजीव उदाहरण बन गया। इसे देखकर लोगों के मन में यह भाव सहज ही उमड़ पड़ा कि मुख्यमंत्री के दिलो-दिमाग में केवल प्रदेश की प्रगति और जनकल्याण का ही संकल्प नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के प्रति उनका गहरा अनुराग भी है।

इवान के पिता श्री अमन गर्ग ने कहा कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री की गोद में देखना उनके परिवार के लिए भावुक, अनमोल और अविस्मरणीय क्षण है। उन्होंने कहा कि यह स्मृति जीवन भर उनके साथ रहेगी। श्री गर्ग ने बताया कि इवान बड़े उत्साह से मुख्यमंत्री और हेलीकॉप्टर को देखने उनके साथ हेलीपैड आया था। मुख्यमंत्री की गोद में जाते ही उसकी खुशी दोगुनी हो गई। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का अपनत्व और बच्चों के प्रति उनका अनुराग सबके सामने आया। उनके इस आत्मीय व्यवहार ने न केवल अमन गर्ग के परिवार का दिल जीत लिया, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों के हृदय में भी अमिट छाप छोड़ दी।

स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, उफनती नदियों और टूटी पुलिया पर हाईकोर्ट सख्त

स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग, विशेषकर दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में है। इन क्षेत्रों में छात्र-छात्राएं टूटी हुई पुलिया और उफनती नदियाँ पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। बच्चों की इस दयनीय स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खुद पहल करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला बच्चों की जान और शिक्षा से जुड़ा है और ऐसी स्थिति को लंबे समय तक नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए पूरी स्थिति पर विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।यह मामला तब उजागर हुआ जब मीडिया रिपोर्ट्स में बच्चों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए,

जिनमें वे जान जोखिम में डालकर पानी भरी नदियाँ पार करते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे को स्वतः संज्ञान में लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि प्रभावित क्षेत्र में स्थायी पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। पहले तकनीकी जांच में 12 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद कांकेर कलेक्टर ने जवाब भेजकर प्रस्ताव में जरूरी संशोधन किए। यह संशोधित डीपीआर 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्हें जोखिम में डालकर शिक्षा के लिए मजबूर करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत और अब तक की पूरी कार्रवाई का नया हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है।

रायगढ़ मेरा परिवार, मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

100 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर संयंत्र और पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध होगी सिंचाई सुविधा

रायपुर।रायगढ़ मेरा परिवार, मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के ग्राम बायंग (कछार) में 38 करोड़ रुपये की लागत से मांड नदी बायंग एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इससे लाभान्वित गांवों में भू-जल संवर्द्धन होगा तथा आवागमन की सुविधा भी बढ़ेगी। एनीकट कम काजवे निर्माण से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर संयंत्र और पाइपलाइन के जरिए सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।मुख्यमंत्री श्री साय ने लोकार्पण कार्यक्रम में ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि रायगढ़ क्षेत्र में जब भी मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही परिवार के बीच आया हूँ। आप सभी ने 20 वर्षों तक आशीर्वाद देकर मुझे सांसद बनाकर दिल्ली भेजा, अब मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने परिवार से मिलने आप सबके बीच आया हूँ। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विगत 20 महीनों में 'मोदी की गारंटी' के तहत अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इनमें धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता, तेंदूपत्ता संग्राहकों को पुनः चरण पादुका वितरण, किसानों को धान बोनस तथा 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रदेश के युवा देख रहे हैं कि जिन्होंने पीएससी परीक्षा में घोटालेबाजी की, वे जेल के अंदर हैं और कुछ जाने की तैयारी में हैं। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार में श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन योजना और बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा की योजना प्रारंभ की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने एनीकट भूमिपूजन के अवसर को बायंग (कछार) गांव के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। अब गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, महतारी वंदन योजना का पैसा समय पर हर महीने मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन तथा डबल इंजन की सरकार में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रायगढ़ क्षेत्र का संसद में पिछले 20 वर्षों से प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे मुख्यमंत्री प्रत्येक गांव के लिए परिवार के सदस्य जैसे हैं। रायगढ़ से सांसद रहते हुए शायद ही ऐसा कोई गांव बचा हो जहाँ मुख्यमंत्री श्री साय न गए हों। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बने मात्र 20 महीने हुए हैं और इस अवधि में अनेक कार्य किए गए हैं। किसानों के एक-एकड़ पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, दो वर्षों का बकाया बोनस, भूमिहीन मजदूरों के खाते में हर साल 10 हजार रुपये की राशि पहुँच रही है। हर गांव में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे हैं। राजमिस्त्री और सेंट्रिंग प्लेट कम पड़ गए हैं, फिर भी लगातार कार्य हो रहे हैं। केवल कछार गांव में ही 180 से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं।

लुत्ती बांध के टूटने पर जताई गहरी नाराज़गी, दुबारा इस तरह की गलती नहीं की जाएगी बर्दाश्त – मुख्यमंत्री

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थित लुत्ती बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री साय ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत रूप से फील्ड में जाकर बांधों सहित अन्य संरचनाओं का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान देने, सभी बांधों की जलभराव क्षमता, वर्तमान सिंचाई स्थिति और आगामी परियोजनाओं की प्रगति आदि के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक दिशाङ्गनिर्देश दिए। साथ ही विशेष रूप से बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का कड़ाई से पालन करने तथा जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने लक्षित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग की अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

रायपुर में इंस्पायर अवार्ड के लिए हुई जिला स्तरीय कार्यशाला

मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कलेक्टर डॉ गौरव सिंह

ज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े शिक्षक और विद्यार्थी करें नवाचार: कलेक्टर डॉ सिंह

रायपुर। इंस्पायर अवार्ड के नॉमिनेशन हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज श्री बालाजी विद्या मंदिर, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह मुख्य अतिथि के रूप संबोधित करते हुए कहा कि जिले एवं ब्लॉक स्तर पर विज्ञान क्लब का गठन किया जाएगा। इन क्लबों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे गुरु की भूमिका निभाकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि आने वाला समय नॉलेज का समय है नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज से सभी शिक्षक अपडेट हो द्य मोबाइल का भरपूर उपयोग ज्ञान लेने के लिए करें क्योंकि मोबाइल संवाद का भी माध्यम है एवं नवाचार के लिए आपको किसी विशेष पद पर होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी रचनात्मक कार्य की सोंच रखते हुए नवाचार कर सकता है। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी होनी चाहिए इसके लिए एक लैब बनाने हेतु जिला प्रशासन पहल कर रहा है। जिला स्तर और विकासखंड स्तर के स्कूलों में साईंस क्लब बनाए जाएंगे। जहां पर वैज्ञानिक-अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने कहा की बच्चों में विज्ञान को लेकर जिज्ञासा और जानने की ईच्छा होनी चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिक अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार कार्य करते हुए आगे बढ़ रहें हैं। इसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताना आवश्यक है। शिक्षक ज्ञानदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चें मोबाईल का प्रयोग ज्ञान लेने के लिए कर रहें है आने वाले समय में आप सभी को टेक्नोलॉजी से जुड़कर कार्य करें ताकि शिक्षकगण अपडेट रहें। इस अवसर पर विज्ञान भारती के प्रतिनिधि श्री नरेश चाफेकर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारती तथा धरसींवा ब्लॉक के शिक्षकगण उपस्थित रहे।

वनमंत्री श्री कश्यप छत्तीसगढ़ रजत जयंती कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण सम्मान समारोह में हुए शामिल

वनमंत्री श्री कश्यप छत्तीसगढ़ रजत जयंती कार्यक्रम

शिक्षक-शिक्षिकाओं को शॉल श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

1 करोड़ 25 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज नारायणपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण सम्मान समारोह एवं छत्तीसगढ़ रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। वन मंत्री श्री कश्यप ने शिक्षक दिवस के अवसर पर एजी आडोटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत शिक्षकों को शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया।

उन्होंने कहा की डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितम्बर के अवसर पर पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरूजनों के आदर्शो का सम्मान करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलकर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे अपने भविष्य को सफल एवं उज्जवल बनाने के लिए प्राथमिक शालाओं के गुरूजनों के द्वारा बच्चों के भविष्य को बनाने के शिक्षा दी जाती है। उनके शिक्षा को जो बच्चे ग्रहण करते है वे अपने जीवन में सफलता हासिल करते है और अपने मंजील तक पहुंचने में कमयाब होते है। उन्होंने ने कहा कि जिला बने 18 वर्ष हो चुका है अभी और कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जिले को विकसित जिला बनाने में जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की सहयोगार्थ भावना से कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे देश में गुरू परमपरा का देश है, शिक्षक बिना स्वार्थ अपने दयित्वो का निर्वहन करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते है गुरू के बिना जीवन ही अधूरे होती है। उन्होंने ताइक्वाण्डो, मलखम्ब एवं स्केटिंग के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले के प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के 04 विद्यालय जो विभिन्न कारणों से बंद थे, इनका नियद नेल्लनार योजना के तहत् इस वर्ष से पुनः संचालन प्रारंभ किया गया है। जिले मे युक्तियुक्तकरण के पश्चात् 66 शासकीय शालाओ में विषयवार शिक्षको की कमी को पूर्ण करने हेतु 140 अतिथि शिक्षको की स्वीकृति डी.एम.एफ मद से प्रदान की गई है। जिले में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित बच्चों के लिए ''स्कूल केइन्ता अभियान'' के तहत् 24 हजार 701 परिवारों का सर्वे कराया गया है, जिसमें 1 हजार 47 शाला त्यागी एवं 1 हजार 295 शाला अप्रवेषी बच्चों को पुनः शाला में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मान और सुविधा की पहल

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप आज जिले में प्रोजेक्ट सेकेंड इनिंग की शुरूआत की गई। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने प्रोजेक्ट सेकेंड इनिंग के अंतर्गत आज शिक्षा विभाग से विगत वर्ष से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं कर्मचारियों से भेंट की। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनों व अन्य वित्तीय देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी अवसर पर कलेक्टर डॉ सिंह ने हाल ही में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए श्री चुन्नीलाल शर्मा को पेंशन आदेश सौंपा। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के पश्चात हर अधिकारी-कर्मचारी नए जिंदगी की शुरूआत करता है। हम आमतौर पर नई पारी कहते है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके प्रकरणों का समाधान जल्द से जल्द हों और उनके सत्व जल्द प्रदान किए जाए।

माताओं-बहनों के सम्मान से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि संभव : मुख्यमंत्री

अब तक कुल 12,376.19 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों तक पहुँची, महिलाओं के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित भव्य कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त का भुगतान किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की 69,15,994 महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1000-1000 रुपये की राशि अंतरित की। कुल 647.13 करोड़ रुपये की यह राशि एक क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके आत्मसम्मान को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आर्थिक सहयोग न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि परिवार की आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने महिलाओं से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कदम उठाती रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों के जीवन में आशा, विश्वास और नई प्रेरणा का संचार कर रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार महिलाओं की बेहतरी और समाज की उन्नति के लिए इसी प्रकार लगातार कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 69 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जा रही है। आज की 19वीं किस्त सहित अब तक कुल 12,376.19 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों तक पहुँचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान कर रही है। यह उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि योजना का प्रभाव न केवल महिलाओं तक सीमित है, बल्कि इससे पूरे परिवार को मजबूती मिल रही है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है।राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं के विकास, सुरक्षा और स्वाभिमान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महतारी वंदन योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी दरों में बदलाव को बताया जनहित में फैसला, कहा- नवरात्रि से मिलेगा फायदा

रायपुर, 05 सितम्बर (आरएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी टैक्स दरों में किए गए संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे आम जनता के लिए लाभकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान होगी, बल्कि व्यापार करने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी।

समाचार एजेंसी से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स दरों में हुए इस बदलाव का असर नवरात्रि से दिखने लगेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे फैसलों से भारत आर्थिक रूप से और अधिक मज़बूत होकर उभरेगा। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम जनहित में है और देश को आगे ले जाने वाला है।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजनांदगांव की ऐतिहासिक पहल, राजनांदगांव जिला प्रशासन ने दी शिक्षा के क्षेत्र में नई सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व पहल की है। जिले के 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निशुल्क नीट और जेईई की तैयारी कराने हेतु दो वर्षीय निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ कल गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं राजनांदगांव लोकसभा सांसद श्री संतोष पांडेय की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। कलेक्टर राजनांदगांव डॉ सर्वेश्वर भुरे ने बताया कि इसके तहत 684 मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए नीट और जेईई की कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान फ़िजिक्स वाला एवं भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ करार किया है। दो वर्षीय कोचिंग विशेष रूप से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए की गयी है।कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क है, जिससे सामान्य परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों को फ़िजिक्स वाला की अध्ययन सामग्री हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी।कक्षाएँ प्रत्येक शनिवार और रविवार को चार घंटे की अवधि के लिए संचालित होंगी।प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर भी जोर दिया जाएगा। जिले को 10 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है ताकि प्रशिक्षण ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से संचालित हो सके। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का समान अवसर उपलब्ध कराना है। गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन से विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ देश के प्रतिष्ठित मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले में नीट और जेईई की निशुल्क कोचिंग शुरू होने पर प्रसन्नता जताई है और कहा है कि राजनांदगांव जिला प्रशासन की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। यह प्रयास हमारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के साथ-साथ उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ का हर मेधावी बच्चा अपनी क्षमता को पहचान सके और उसे आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले। राजनांदगांव की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रेरणा और विद्यार्थियों के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।

एक सप्ताह में तीन बड़े घरों में चोरी, लाखों की नकदी और जेवरात गायब

रायपुर। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर और डीडी नगर थाना क्षेत्रों में बीते एक सप्ताह के भीतर चोरी की तीन बड़ी वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। कोटा टीचर्स कॉलोनी, अश्विनी नगर और सुंदरम विहार क्षेत्रों में घरों का ताला तोड़कर लाखों रुपये नकद और सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया गया है। सभी घटनाएं तब हुईं जब मकान मालिक घर से बाहर थे, जिससे चोरों को वारदात को अंजाम देने का पूरा मौका मिला।

पहली घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की है, जहां स्पीच थैरेपिस्ट मोहम्मद सरताज के कोटा टीचर्स कॉलोनी स्थित घर में चोरों ने करीब सात लाख रुपये नकद और कीमती गहने चुरा लिए। सरताज 29 अगस्त को टीम के साथ विशाखापट्टनम दौरे पर गए थे। 31 अगस्त को सफाई के लिए आई नौकरानी ने टूटा ताला देखा और 1 सितंबर को सरताज के लौटने पर चोरी की जानकारी सामने आई। उन्होंने तत्काल थाना सरस्वती नगर में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी वारदात डीडी नगर थाना क्षेत्र के डंगनिया में हुई, जहां अश्विनी नगर स्कूल की व्याख्याता तारिणी वर्मा के घर 26 से 28 अगस्त के बीच चोरों ने धावा बोला। ताले तोड़कर चोरों ने करीब ढाई से तीन लाख रुपये नकद और साढ़े चार लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने चोरी किए। चोरी गए नकदी को स्कूल की फीस बताया गया है। गहनों में दो सोने के हार, आठ अंगूठियां, मंगलसूत्र, चेन, कंगन, झुमके, टॉप्स और चांदी के जेवर शामिल हैं। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक बैग लेकर घर से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। सरस्वती नगर टीआई नरेंद्र साहू ने बताया कि मामले की जांच तेज़ी से की जा रही है। तीसरी वारदात डीडी नगर थाना क्षेत्र के सुंदरम विहार की है, जहां अमित सोनी ने अपने भाई सुमित कुमार के किराए के मकान में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरा परिवार 15 अगस्त से हरियाणा गया हुआ था।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

युवाओं के भविष्य की चिंता करती मोदी सरकार

युवाओं को अपना हित देखना आवश्यक है। देश के युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग की लत बढ़ती चली गई है। इस कारण हर साल 45 करोड़ लोग पैसा गंवाते हैं। ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने के लिए घरों के भीतर कलेश और हिंसा के मामले बढ़ते चले गए हैं। कई आत्म-हत्याओं की खबरें भी हर साल आती हैं। लोगों की इसी बदहाली की कीमत पर गेमिंग इंडस्ट्री फूल-फल रही है। उसके संचालकों का दावा है कि यह कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि इस इंडस्ट्री में दो लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस कारोबार के जरिए इंडस्ट्री हर साल 20 हजार करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को देती है। मगर सरकार को ऐसी दलीलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिलहाल उसने राजस्व पर सामाजिक हित को तरजीह देने का रुख लिया है, जिस पर उसे कायम रहना चाहिए। सामाजिक बुराई को फैलाने वाले हर कारोबार से कुछ लोगों की रोजी-रोटी चलती है। बुराई को जब कभी रोका जाएगा, ऐसे लोगों को नुकसान होगा।

मोहब्बत करना कब से कसूर हो गया?

जो नजरों से से दूर हो गया ।
समझों दिलों से दूर हो गया।।

सांझ मिलने का किया वादा जिसने ।
वह तपती दोपहर में कापूर हो गया ।।।

चलो धीमें कदमों से चलतें हैं दूर तलक ।
कम फासला देखो कितना दूर हो गया।।

कश्तियां डगमगाती रही लहरों में।
लहरो का मचलना दस्तूर हो गया।।

दूर तक चिलचिलाती धूप ही धूप हैं ।
इक हंसी शहर कितना बेनूर हो गया।।

क्यों पत्थर फेकते हो दीवाने पर संजीव,
मोहब्बत करना कब से कसूर हो गया।

- संजीव ठाकुर ।

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya_ Vaidik_Netritva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-Bhrasht Tantra

Silent Assassins Jan11,1966

Accursed & Jihadi Neighbour

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना देगी युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान

डॉ. मनसुख मांडविया

भारत की विकास गाथा हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में करोड़ों श्रमिकों के समर्पण और क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में, भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने वैश्विक पटल पर अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है और इसमें इसके मानव संसाधन की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सफलता की कहानी को बल देने वाला तथ्य यह है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आरबीआई-केएलईएमएस के अनुसार, जहां 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। औपचारिकीकरण में भी तेजी आई है, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले सात वर्षों में लगभग आठ करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बढ़तोरी होना भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में, केवल 19 प्रतिशत भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो चुकी है और 94 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आए हैं, जिससे भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने वाला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज विस्तार में से एक माना है।

यह स्पष्ट है कि राष्ट्र का भविष्य न केवल जीडीपी वृद्धि की गति से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा और अपने युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति, आपूर्ति-श्रृंखला में बदलाव और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली कई अन्य कमजोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर खड़ा है।

हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे देता है, जबकि पश्चिमी देशों में आबादी वृद्ध होती हो रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी इसकी युवा शक्ति को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। फिर भी, पिछली सरकारों के अधीन, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। अमृत काल में, जब हम 2047 तक एक विकसित भारत के विजन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने कार्य स्पष्ट हैः हमें संभावना से समृद्धि की ओर बढ़ना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, रोजगार अब केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं रह गया है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करें, उन्हें वित्तीय साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित हों। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभ वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है।

इसी चुनौती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच के अंतर को पाटने के लिए, 15 अगस्त को लाल क़िले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तुत और प्रधानमंत्री जी के अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित यह योजना पैमाने और डिजाइन, दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इनमें से दो करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे।

योजना के दो स्तंभः पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को सहायता

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को इसकी संरचना ही अलग बनाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के विपरीत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता की दोहरी चुनौती का एक साथ समाधान करती है। भाग 'ए' के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दो किश्तों में 15,000 रुपए तक) और भाग 'बी' के तहत नियोक्ताओं (प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक) को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह श्रमिकों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करता है।

इस योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए कर्मचारियों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एक औपचारिक, सुरक्षित और उत्पादक श्रम बाजार की ओर एक संरचनात्मक कदम है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पर अतिरिक्त ध्यान, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और प्रयास है।

समावेशी और सतत विकास को गति देना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, योजना-आधारित पहलों से हटकर एक व्यापक रोजगार प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह पूर्व की पहलों से मिली सीख पर आधारित है, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई), राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मेक इन इंडिया जैसी वर्तमान योजनाओं का पूरक है और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में काम की बदलती प्रकृति को पहचानती है।

श्रमिकों और नियोक्ताओं, दोनों को प्रोत्साहन देकर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यह मान्यता देती है कि रोजगार सृजन एक साझा जिम्मेदारी है। भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे - यहां तक कि सबसे छोटा उद्यम और कार्यबल में शामिल होने वाला सबसे नया व्यक्ति भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में भागीदार बने।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाः नए भारत की नींव

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं अधिक बढ़कर है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यह पहल विकसित भारत के विजन को साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहां हर युवा को सार्थक रोजगार मिले, हर काम में सम्मान हो और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले।

रोजगार निर्माण सही मायने में राष्ट्र निर्माण है। इस पहल के साथ, मोदी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं रहेगी और कोई भी युवा अवसर से वंचित नहीं रहेगा। हम सब मिलकर भारत की युवा शक्ति को नई उड़ान दे रहे हैं और उनके माध्यम से, विकसित भारत के सपने को भी नई गति प्रदान कर रहे हैं।

लेखक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत सरकार हैं

भारत नियति के द्वार पर खड़ा

श्रुति व्यास

लंदन के द इकॉनोमिस्ट ने ठिक लिखा कि यदि अमेरिका भारत को अलग-थलग करता है, तो यह उसकी ऐतिहासिक भूल होगी। जबकि भारत के लिए अपनी सुपरपावर बनने की दावेदारी को परखने का यह मौका है। पहली नज़र में वाक्य सुकून देता है – जैसे अमेरिका ग़लती करेगा अगर डगमगाया, और भारत नियति के द्वार पर खड़ा है। पर ध्यान से सुनें तो यह तारीफ़ नहीं, टालमटोल है। सुपरपावर-इन-वेटिंग यानी अभी नहीं। याकि महज नारे जिनमें जान नहीं, प्रदर्शन जिसमें ताक़त नहीं। एंकर की तरह तीन शब्द हमें बाँध देते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने ही भविष्य की कतार में फँसा है, हिचकिचाहट में अटका है। इतिहास में दर्ज होता है, ताक़त के रूप में नहीं, बल्कि फुटनोट की तरह- इन वेटिंग।

यह नहीं कि भारत कभी इंतज़ार में नहीं रहा। मोटामोटी हर प्रधानमंत्री ने ताकत और फुटनोट की खाई को पाटने की कोशिश अपने-अपने ढंग से की है– अपूर्ण रूप से, लेकिन एक निशान छोड़ते हुए। बस आज वह इन-वेटिंग इतना जाहिर, स्पष्ट, इतना चौड़ा हो गया है कि आकांक्षा और आस्था के बीच की दूरी लगभग असंभव लगती है।

आज़ादी के समय नेहरू ने नियति से साक्षात्कार की बात की थी – एक उपनिवेश से आगे बढ़ने का साहस। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण से लेकर पोखरण तक भारत की ताक़त दिखाई। नरसिंहाराव ने 1991 में बंद अर्थव्यवस्था की दीवार तोड़ी और उदारीकरण की नींव रखी। मनमोहन सिंह ने शांति से न्यूक्लियर डील, स्थिर विकास और वैश्विक बाज़ार में भारत की स्थिति को मज़बूत किया। हर दौर अपूर्ण था, पर आकांक्षा जीवित थी। यह भावना केवल सत्ता गलियारों में नहीं, बल्कि भारत के मध्यमवर्ग की कल्पना में भी थी।

फिर आए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आकांक्षा को तमाशे और नारों में लपेट दिया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अमृत काल – नियति की भाषा को नए ज़माने के लिए पैक किया। कुछ समय के लिए लगा कि अब इन वेटिंग ख़त्म होगा, भारत महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। यह स्वप्न स्वर्णिम लगा।

पर सपनों का रंग नहीं होता और न कोई विचारधारा। वे या तो साहसी होते हैं या हिचकिचाए हुए। रूस सोवियत अतीत को पुनर्जीवित करना चाहता है। चीन अपने ही साये से बड़ा होना चाहता है। उनकी आकांक्षा कठोर है, बलिदान से तराशी हुई। भारत की आकांक्षा भावुक है, नारों में ढह जाती है। हम खुद को यह कहकर सांत्वना देते हैं कि हमारी चढ़ाई लोकतांत्रिक होगी, इसलिए श्रेष्ठ होगी। पर बिना त्याग और साहस के, सपने रेटरिक में बदल जाते हैं।

पर आज का भारत क्या सपने देखना छोड़ नहीं चुका है?

अपने चारों ओर देखिए। आपका घर, गाड़ी, सड़क, दफ़्तर की मेज़, टिफ़िन का खाना, बैंक का मैसेज – यही है हमारी ज़िंदगी की लय। सुरक्षित, स्थिर, पूर्वानुमेय। यह आरामदायक है, लेकिन आकांक्षाएँ अब सुपरपावर बनने की ऊँचाई पर नहीं, बल्कि मध्यमवर्गीय सुरक्षा की छत पर अटकी हैं – नौकरी, ईएमआई, सालाना छुट्टी। 21वीं सदी में भी हम जीने को महत्वाकांक्षा समझते हैं, स्थिरता को नियति। इसी चुप्पी में छिपा है वह सच, कि भारत अब भी सुपरपावर इन वेटिंग है।

नई सदी ने ताक़त का नक्शा बदल दिया है। अब शक्ति का स्रोत न साम्राज्य है, न कच्चा माल, बल्कि मनुष्य की क्षमताएँ और उन्हें संभालने वाला ढाँचा। राष्ट्र नारों से नहीं, बल्कि इस बात से उठते हैं कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, शोध और सड़कों में कितना निवेश करते हैं। प्रतियोगिता अब भूगोल की नहीं, प्रतिभा की है।

इन वेटिंग की कहानी सिर्फ़ नीतिगत काग़ज़ों या जीडीपी आँकड़ों में नहीं, बल्कि ज़मीनी शहरों में दिखती है – और मुंबई से स्पष्ट कोई दूसरा शहर नहीं है। मगर यहाँ महत्वाकांक्षा और असमानता भयावह आमने-सामने खड़ी हैं। 1970ङ्क80 के दशक में यह शहर हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार जैसे अंडरवर्ल्ड डॉनों का था। बाद में दाऊद ने अपराध में वैश्विक हल्लाबनाया। आज दौर बदला है। अब अंबानी और अदानी की तूती हैं। और इन्हें मोदी राज में राष्ट्रवाद की भाषा में आत्मनिर्भर भारत के महानायक कहा जा रहा है। जो उद्यमशीलता पहले गली-मोहल्ले से फलती-बढ़ती थी, वह अब राज्य की चुप्पी और नीति की कृपा से प्रतिमान बन रहे हैं।

पर जिस राष्ट्र में अरबपति मसीहा बनते हैं, वह धन को महत्ता से और इसी के गरूर में ग़लतफ़हमी में फंसता है। व्यापारी घरानों से औद्योगिकीकरण और उससे रोज़गार व वास्तविक आर्थिक शक्ति नहीं बनती। फिर शिक्षा खोखली और टूटी हुई है, बुनियादी ढाँचा कमज़ोर है। और जब संकट आता है तो सुधारों की जगह हिंदू राष्ट्रवाद की डुगडुगी बनती हैं। या सरकार नया आख्यान गढ़ती है। जैसे ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ़ से बाज़ार हिला, तो ईवाई की रिपोर्ट आई। जबरदस्ती बेवक्त का हल्ला कि 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। काग़ज़ पर वादा है – ताक़त, उपभोग, पूँजी। पर ज़मीन पर सवाल वही है- क्या आर्थिकी का बड़ा आकार भीड़ में जी रहे आम भारतीय को गरिमा देगा?

जब तक असमानता के कैंसर से निजात नहीं है, मानव पूँजी नहीं बनेगी, ढाँचा नहीं सुधरेगी, भारत आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि विरोधाभासों में फंसा रहना है। अर्थव्यवस्था का आकार भले बढ़े पर समृद्धि के छोटे टापू रहेंगे। विकास की बातें और वंचना का सागर। हम फुटनोट ही बने रहेंगे और इन तीन शब्दों में कैद रहेंगे – सुपरपावर इन वेटिंग।

यह निजी विचार है।

स्वस्थ भारत की यही पहचान सही रहे पोषण खान-पान

- सुरेश सिंह बैस शाश्वत

हमारे देश में हर वर्ष 1 से 7 सितम्बर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ आहार, संतुलित पोषण, और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। यह सप्ताह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पोषण अभियान का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत अमेरिका में 1975 में हुई थी, लेकिन भारत में इसे पहली बार 1982 में मनाया गया। उस समय भारत में कुपोषण और कुपोषण से जुड़ी बीमारियों की दर काफी अधिक थी। इसके समाधान हेतु सरकार ने यह सप्ताह लोगों को पोषण संबंधी जानकारी देने के लिए आरंभ किया।

इस सप्ताह का खासकर यह उद्देश्य है। संतुलित आहार की महत्ता को समझाना। कुपोषण, अल्पपोषण और अतिपोषण जैसे मुद्दों पर जनजागरूकता फैलाना। बच्चों, महिलाओं और वृद्धों के पोषण संबंधी विशेषआवश्यकता पर ध्यान देना। स्वास्थ्यकर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

स्थानीय खाद्य पदार्थों की उपयोगिता को बढ़ावा देना। सामान्य तौर पर देखें तो पोषण का तात्पर्य ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से है जो हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि प्रदान करें। संतुलित पोषण हमें न केवल बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होता है।

जहाँ तक देश की बात करें तो भारत एक विकासशील देश है और यहां पोषण से संबंधित कई समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं जैसेबच्चों में कुपोषणः यूनिसेफकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषित हैं।

महिलाओं में एनीमिया (रक्त की कमी): विशेषकर गर्भवती महिलाओं में यह समस्या सामान्य है। अज्ञानता और गरीबीः सह।अज्ञानता और गरीबीः सही जानकारी और संसाधनों की कमी के कारण लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते।जंक फूड का बढ़ता चलनः शहरी क्षेत्रों में फास्ट फूड की आदत भी पोषण असंतुलन को जन्म देती है। इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। इसके तहत निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:आंगनवाड़ी केंद्रों की सक्रिय भागीदारी। 'पोषण ट्रैकर' जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग, जन भागीदारी के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन एवं 'पोषण माह' और 'पोषण पर्व' जैसे आयोजन किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की गतिविधियों में इस सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, आंगनवाड़ी केंद्रों, और स्वास्थ्य केंद्रों में कई प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं:,पोषण प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच शिविर, खाद्य मेला, संबंधित जानकारी और संसाधनों की रंगोली, पोस्टर आदि प्रतियोगिता सहित जनजागरूकता रैलियाँ, स्वस्थ रेसिपी प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सरकार, समाज, संस्थाएँ और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति अपने भोजन और पोषण को लेकर सजग हो जाए, तो भारत को एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।

÷सही पोषण, देश रोशन÷
÷पोषण ही जीवन है।। ÷
÷स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन,
पोषण की जरूरत हर
एक की पहचान
संतुलित आहार से
बनाएं अपना जीवन,
स्वस्थ भारत का सपना
साकार करें सब मिलकर।।

भारत वर्ष 2030 तक विश्व के शीर्ष 10 जहाज निर्माण करने वाले देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा

पीआईबी

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज यहां वी.ओ. चिदंबरनार (वीओसी) बंदरगाह पर भारत का पहला पोर्ट-आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना पर उद्घाटन किया, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3.87 करोड़ की लागत से निर्मित 10 Nm/घंटा क्षमता वाली इस पायलट सुविधा से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग पोर्ट कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों और एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को बिजली प्रदान करने में किया जाएगा। इस शुभारंभ के साथ, वीओसी पोर्ट देश का पहला हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पोर्ट बन गया है।

श्री सोनोवाल ने 35.34 करोड़ की लागत से 750m³ क्षमता वाली एक पायलट हरित मेथनॉल बंकरिंग और ईंधन भरने की सुविधा की आधारशिला भी रखी। कांडला और तूतीकोरिन के बीच प्रस्तावित तटीय हरित शिपिंग गलियारा के इस पहल से वीओसी पोर्ट को दक्षिण भारत का एक प्रमुख हरित बंकरिंग केन्द्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ÷विकसित भारत 2047 का मिशन गति, पैमाना, स्थिरता और

आत्मनिर्भरता का संगम है। आज शुरू की गई परियोजनाएं हजारों रोजगार उत्पन्न करेंगी, वैश्विक निवेश आकर्षित करेंगी और तमिलनाडु को भारत की आर्थिक आकांक्षाओं का प्रमुख भागीदार बनाएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हम वर्ष 2030 तक विश्व के शीर्ष 10 और वर्ष 2047 तक शीर्ष 5 जहाज़ निर्माण करने वाले देशों में शामिल होने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर नए कदम बढ़ा रहे हैं।÷ अन्य परियोजनाओं में 400-KW की रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया, जिससे पोर्ट की रूफटॉप सोलर क्षमता बढ़कर 1.04-मेगावॉट तक पहुंच जाएगी, जो भारतीय बंदरगाहों में सबसे अधिक है। साथ ही ?24.5-करोड़ की लागत से कोल जेट्टी-ढ्ढ को पोर्ट स्टैक यार्ड से जोड़ने वाला लिंक कन्वेयर शुरू किया गया है, जिससे दक्षता में 0.72-एमएमटीपीए की वृद्धि होगी।

केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 6-मेगावॉट पवन ऊर्जा परियोजना, ?90 करोड़ की मल्टी-कार्गो बर्थ, 3.37-किमी लंबी चार-लेन सड़क और तमिलनाडु समुद्री विरासत संग्रहालय की आधारशिला भी रखी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु के तीन प्रमुख बंदरगाहों– चेन्नई, कामराजार और वीओसी – में सागरमाला के तहत परिवर्तनकारी विकास हुआ है।पिछले 11 वर्षों में ?93,715 करोड़ लागत की 98 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से 50 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, ÷यह एक अद्वितीय प्रगति है। सिर्फ इन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिए ही ?16,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है।÷

केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वतंत्रता सेनानी वी.ओ. चिदंबरनार की 154वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री सोनोवाल कहा, ÷हम वीओसी की उस विरासत से गहराई से प्रेरित हैं, जिन्होंने शिपिंग के माध्यम से स्वदेशी भावना को जगाया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हम उस भावना को हरित ऊर्जा, नवाचार और आत्मनिर्भरता के साथ मजबूती प्रदान करते हुए शिपिंग और पोर्ट क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं।÷ मंत्री जी ने तमिलनाडु और थूथुकुडी के लोगों को उनके पूरे समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। श्री सोनोवाल ने कहा, ÷हम यहां जो भी परियोजनाएं अपना रहे हैं, आप लोगों के विश्वास और सहयोग से हम उन्हें समय पर पूरा कर पा रहे हैं। मंत्रालय इसी तरह कार्य कर रहा है– गति, पैमाना और भारत के विकास की प्रतिबद्धता के साथ।÷

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नई दिल्ली स्थित दिल्ली सचिवालय में रामलीला समितियों के साथ बैठक के दौरान।

कश्मीर के श्रीनगर के दक्षिण में पंपोर में एक निर्माण कंपनी का प्रवेश द्वार बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है।

आईईपीएफए ने जीवन को आसान बनाने के लिए कम राशि वाले दावों के लिए दस्तावेज प्रक्रिया को सरल बनाने की पेशकश की

पीआईबी

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और कम राशि वाले दावों की दस्तावेज प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन किया था। इस पहल से समय सीमा में उल्लेखनीय कमी आने, पारदर्शिता में सुधार होने और निवेशकों को परेशानी मुक्त सेवाएँ मिलने की उम्मीद थी। समिति में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), और भारतीय रजिस्ट्रार संघ (आरएआईएन) के प्रतिनिधि शामिल थे।

जीएसटी सुधार 2030 तक देश को 350 अरब डॉलर की कपड़ा अर्थव्यवस्था बनाने में होंगे मददगार : केंद्र

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार के अनुसार, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक छलांग हैं, जो 2030 तक देश को 350 अरब डॉलर की कपड़ा अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उत्प्रेरक का काम करेंगे।

कपड़ा मंत्रालय ने इन सुधारों को लागू करने के लिए उद्योग के हितधारकों, निर्यातकों, कारीगरों और उद्यमियों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

इन ऐतिहासिक सुधारों से लागत कम होने, संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने, रोजगार को बनाए रखने और रेशे से लेकर फैशन और विदेशी बाजारों तक, संपूर्ण कपड़ा वैल्यू चेन को मजबूत करने की उम्मीद है।

ये सुधार प्रधानमंत्री के दूरदर्शी 5एफ फॉर्मूले (फ्रॉम फाइबर टू फैशन टू फॉरेन

मार्केट) के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं, जिसका उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल टेक्सटाइल पावरहाउस के रूप में स्थापित करना है। कपड़ों में जीएसटी को रेशनलाइज बनाने से विकृतियां दूर होंगी, उत्पादन लागत कम होगी, मांग बढ़ेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

ये सुधार रेशे के स्तर पर विसंगतियों को दूर करते हैं, धागे और कपड़े के स्तर पर लागत कम करते हैं, परिधानों की सामर्थ्य में सुधार करते हैं, खुदरा स्तर पर मांग को पुनर्जीवित करते हैं और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, ये उपाय भारत की रेशा-तटस्थ नीति को मजबूत प्रोत्साहन देते हैं, जिससे कपास और मानव निर्मित क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित होता है।

रेडीमेड कपड़ों और मेड-अप वस्तुओं पर 2,500 रुपए प्रति पीस (पहले 1,000 रुपए) तक की 5 प्रतिशत जीएसटी दर, किफायती परिधानों को, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न-आय वाले परिवारों के लिए, सस्ता बनाती है।

इससे टियर 2 और 3 शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग में सुधार की उम्मीद है।

मंत्रालय ने कहा, परिधान उद्योग की श्रम-प्रधान प्रकृति को देखते हुए खासकर सिलाई, टेलरिंग और फिनिशिंग इकाइयों में महिलाओं के लिए उच्च मांग से रोजगार बना रहेगा और बढ़ेगा। यह कदम मेक इन इंडिया ब्रांडों को भी समर्थन देगा, जिससे उन्हें कम और मध्यम-मूल्य वाले क्षेत्रों में सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

रेशों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और सूत पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

मानव निर्मित रेशों (एमएमएफ) के उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी लघु और मध्यम इकाइयों की है, इसलिए इस कटौती से लागत का दबाव कम होगा, नकदी प्रवाह मजबूत होगा और भारतीय एमएमएफ-आधारित परिधान वैश्विक स्तर पर अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे सिंथेटिक वस्त्रों और एमएमएफ परिधानों के केंद्र के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा को बल मिलेगा।

कालीनों और फर्श कवरिंग पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे भदोही और श्रीनगर जैसे समूहों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक शिल्प को मजबूती मिलेगी और घरेलू बाजारों में सामर्थ्य में सुधार होगा।

सहकारिताओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वस्तु सेवा कर (GST) दर में व्यापक कटौती

10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को होगा लाभ

दूध और पनीर पर कोई त्रस्ञ नहीं, मक्खन और घी पर 5त्र त्रस्ञ

किफायती दुग्ध उत्पाद पोषण सुरक्षा बढ़ाएंगे और दुग्ध सहकारिताओं को लाभ पहुंचाएंगे

केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में व्यापक कमी की घोषणा की है, जिससे सहकारी संस्थाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों सहित 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को सीधा लाभ होगा। ये सुधार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे, उनके उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, उनके उत्पादों की माँग और उनकी आय बढ़ाएंगे। यह ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारिताओं को प्रोत्साहित करेगा और लाखों परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुएँ किफायती रूप से उपलब्ध कराएगा। जीएसटी दर में कटौती खेती और पशुपालन में लगी सहकारिताओं को लाभ पहुँचाएगी, टिकाऊ खेती की प्रथाओं को बढ़ावा देगी और छोटे किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सीधा लाभ देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाये गये #Ne&tGenGST रिफ ार्म का पूरे दुग्ध सहकारी क्षेत्र ने स्वागत किया है, जिसमें अमूल जैसे सबसे बड़े सहकारी ब्रांड भी शामिल हैं।

दुग्ध क्षेत्र में किसानों और उपभोक्ताओं को वस्तु सेवा कर में सीधे राहत दी गई है। दूध और पनीर, चाहे ब्रांडेड हों या बिना ब्रांड के, को जीएसटी से मुक्त किया गया है।

मक्खन, घी और ऐसे ही अन्य उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लोहे, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कनस्तरों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इन उपायों से दुग्ध उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, दुग्ध किसानों को सीधी राहत मिलेगी और विशेषकर दूध प्रसंस्करण में लगी महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वयं सहायता समूह को मजबूती मिलेगी। किफायती दुग्ध उत्पाद घर-घर में आवश्यक प्रोटीन और वसा स्रोत उपलब्ध कराएंगे और दुग्ध सहकारिताओं की आय बढ़ाएँगे।

खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू वस्तुओं में बड़ी राहत दी गई है। चीज़, नमकीन, मक्खन और पास्ता पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जैम, जेली, खमीर, भुजिया और फलों का गूदा/जूस आधारित पेय पदार्थ अब 5% जीएसटी पर आएंगे। चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और कॉफी पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

कम जीएसटी से खाद्य पदार्थों पर घरेलू खर्च घटेगा, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में माँग बढ़ेगी और खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध सहकारिताओं की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध प्रसंस्करण सहकारिताएँ तथा निजी डेयरियाँ मजबूत होंगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही पैकिंग पेपर, डिब्बे और पेटियों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सहकारिताओं और खाद्य उत्पादकों के लिए लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत कम होगी।

कृषि यंत्र क्षेत्र में, 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ट्रैक्टर अधिक किफायती होंगे और इसका लाभ केवल फसल उत्पादक किसानों को ही नहीं बल्कि पशुपालन और मिश्रित खेती करने वालों को भी मिलेगा, क्योंकि इनका उपयोग चारे की खेती, चारे के परिवहन और कृषि उत्पाद प्रबंधन में किया जा सकता है। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य अनेक पुर्जों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे लागत और घटेगी और सहकारिताओं को सीधा लाभ होगा।

उर्वरक क्षेत्र में, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रमुख कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उल्टा कर ढांचा सुधरेगा, उर्वरक कंपनियों की इनपुट लागत घटेगी, किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी और बुवाई के समय पर किफ ायती उर्वरक उपलब्ध होंगे। इसका सीधा लाभ सहकारिताओं को होगा। इसी प्रकार, बारह बायो-पेस्टीसाइड और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जैव-आधारित कृषि इनपुट अधिक किफायती होंगे, किसान रासायनिक कीटनाशकों से हटकर बायो-पेस्टीसाइड की ओर बढ़ेंगे, मिट्टी की सेहत और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी, और छोटे जैविक किसानों तथा एफपीओ को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन के अनुरूप है और सहकारिताओं को भी लाभान्वित करेगा।

वाणिज्यिक वाहनों में, ट्रक और डिलीवरी वैन जैसे मालवाहक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रक भारत की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं और लगभग 65–70% माल यातायात का वहन करते हैं। इससे ट्रकों की पूंजीगत लागत घटेगी, प्रति टन-किलोमीटर भाड़ा कम होगा और इसका प्रभाव कृषि उत्पादों की ढुलाई को सस्ता बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में दिखाई देगा। साथ ही मालवाहक वाहनों के थर्ड-पार्टी बीमा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ढ्ढञ्जष्ट) की सुविधा भी दी गई है, जिससे इन प्रयासों को और बल मिलेगा।

शिल्प समागम मेला: कला, शिल्प और संस्कृति का उत्सव

पीआईबी

आज से बेंगलुरु में बहुप्रतीक्षित शिल्प समागम मेला 2025 की शुरुआत हुई। इसमें भारत की शिल्प और संस्कृति की असाधारण विरासत का जीवंत रूप देखा गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 'ट्यूलिप' (ट्रेडिशनल आर्टिसन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम) के सहयोग से आयोजित यह मेला 5 से 14 सितंबर 2025 तक फ्रीडम पार्क, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के संस्करण में कारीगरों के हस्तशिल्प के 75 स्टॉल हैं। इनमें जटिल धातु शिल्प, लकड़ी की कलाकृतियां, बेंत और बांस के उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और 13 से अधिक राज्यों के हस्तनिर्मित बहुमूल्य उत्कृष्ट कृतियों का प्रदर्शन किया गया है। यह मेला भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को दर्शाता है, साथ ही एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में भी कार्य करता है, जहां कारीगर शहरी और अंतरराष्ट्रीय खरीददारों के साथ जुड़ते हैं। शिल्प समागम मेला अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सफाई मित्रों सहित विविध समुदायों के कारीगरों के कौशल पर प्रकाश डालता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज मेले का उद्घाटन किया।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

'वैश्विक व्यापार के द्वार : निर्यात प्रोत्साहन एवं ICD विकास' विषय पर संवाद सत्र

पीआईबी

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), छत्तीसगढ़ राज्य परिषद द्वारा हाल ही में रायपुर में ÷वैश्विक व्यापार के द्वारः निर्यात प्रोत्साहन एवं ढ्ढष्ठ विकास÷ विषय पर एक महत्वपूर्ण संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार सुलभता, नीतिगत समर्थन एवं वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के प्रभावों पर विचार-विमर्श करना था। कार्यक्रम में 140 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति रही, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति विशेषज्ञ एवं लॉजिस्टिक्स और व्यापार क्षेत्र के प्रमुख भागीदार शामिल हुए।

सत्र की शुरुआत श्री संजय जैन, अध्यक्ष, CII छत्तीसगढ़ राज्य परिषद एवं प्रबंध निदेशक, RSV E&im Pvt. Ltd. द्वारा स्वागत वक्तव्य के साथ हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की वैश्विक व्यापार में भूमिका पर प्रकाश डाला और विशेष रूप से जापान जैसे विदेशी बाजारों के साथ व्यापारिक अवसरों को रेखांकित किया।

डॉ. सौगात मुखर्जी, प्रधान सलाहकार, CII ने वैश्विक व्यापार में नीति अनुरूपता और बाजार सुलभता की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए, जो CII की राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप है। उन्होंने CII की मार्केट फैसिलिटेशन सर्विसेज (MFS) पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी, जो व्यवसायों के विस्तार योजनाओं को समर्थन देने के

लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक अनूठी सेवा है। अब तक ख्स्नस् के माध्यम से 20 से अधिक देशों में 50 से अधिक उत्पादों के लिए सहयोग प्रदान किया गया है, जिनमें से 75त्न से अधिक परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

मुख्य वक्ता के रूप में श्री अमित चौधरी, संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, रायपुर ने निर्यात प्रोत्साहनों एवं राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो (ढ्ढष्ठ) के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के माध्यम से व्यापारियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बेहतर एकीकरण हेतु सक्षम बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

श्री विमल प्रुथि, पार्टनर – इंडिया ग्लोबल ट्रेड एंड कस्टम्स (EY) ने अमेरिकी टैरिफनीतियों और उनके भारतीय निर्यातकों पर प्रभावों पर जानकारी साझा की और निर्यात रणनीति को पुनः परिभाषित करने हेतु उपयोगी सुझाव दिए।

श्री भावेश मित्तल, संयोजक, CII छत्तीसगढ़ वित्त एवं कराधान पैनल एवं पार्टनर, HNA & Co LLP ने GST 2.0 के संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला और इससे जुड़े नियमों व अनुपालन की दिशा में उद्योगों को जागरूक किया।

कार्यक्रम का समापन संवादात्मक ओपन हाउस सत्र के साथ हुआ, जिसके पश्चात श्री बजरंग गोयल, उपाध्यक्ष, CII छत्तीसगढ़ राज्य परिषद एवं निदेशक, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और व्यापार सुलभता से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद की प्रतिबद्धता को दोहराया।

कलिंगा विश्वविद्यालय में अपशिष्ट अनुकूलन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

नया रायपुर,

एआईसीटीई-अटल वाणी के तत्वावधान में कलिंगा विश्वविद्यालय ने ÷अपशिष्ट अनुकूलन और स्वच्छ प्रौद्योगिकीः ठोस और ई-अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण÷ विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सेमिनार में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों को टिकाऊ अपशिष्ट समाधानों और नवीन प्रौद्योगिकियों पर गहन चर्चा के लिए एक मंच पर लाया गया, जो एक स्वच्छ भविष्य को आकार दे सकते हैं।

कलिंगा विश्वविद्यालय में अपशिष्ट अनुकूलन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर एआईसीटीई-अटल वाणी राष्ट्रीय संगोष्ठी न केवल वैज्ञानिक आदान-प्रदान के लिए एक मंच था, बल्कि अंतर-सांस्कृतिक सहयोग का उत्सव भी था। छत्तीसगढ़ में आयोजित इस सेमिनार में तमिलनाडु के प्रतिष्ठित व्याख्याताओं ने भाग लिया, जो शैक्षणिक संवाद को समृद्ध बनाने के लिए विविध क्षेत्रों को एक साथ लाने के एआईसीटीई के दृष्टिकोण का प्रतीक था और विषय-वस्तु को द्विभाषी (अंग्रेजी और तमिल) रूप में प्रस्तुत किया गया था।

सेमिनार की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आईएएस, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के उद्घाटन भाषण से हुई, जिन्होंने ÷ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः चुनौतियां और अवसर÷ पर एक विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया। डॉ. प्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी भारत को प्रतिदिन 150,000 टन से अधिक नगरपालिका कचरे के प्रबंधन की चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ÷चुनौती केवल निपटान में ही नहीं, बल्कि अवसरों की पहचान करने में भी है–रीसाइक्लिंग, कम्पोस्ट बनाने और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के माध्यम से कचरे को धन में बदलना। एक सर्कुलर माइंडसेट शहरी कचरे को एक दायित्व से एक परिसंपत्ति में बदल सकता है।÷

मुख्य अतिथि, श्री गुरुनंथन, आईएफएस (मुख्य वन संरक्षक, भूमि प्रबंधन) ने ÷स्थायित्व के लिए प्रमुख रणनीतियां - एक समग्र परिप्रेक्ष्य÷ पर अपना सत्र शुरू किया। अपने दशकों के प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करते हुए, उन्होंने एकीकृत नीतियों, सामुदायिक भागीदारी और हरित नवाचारों के महत्व पर प्रकाश डाला। ग्रीनलिंक एनालिटिकल एंड रिसर्च लेबोरेटरी के निदेशक डॉ. एम. पलानिवेल ने ÷जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट संबंध÷ विषय पर एक आकर्षक व्याख्यान दिया। उन्होंने अनुचित अपशिष्ट निपटान और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच परस्पर निर्भरता की ओर ध्यान आकर्षित किया। एवीसी कॉलेज (स्वायत्त) के सहायक प्रोफेसर और शोध सलाहकार, डॉ. एस. जयकुमार ने ÷अपशिष्ट प्रणालियों में स्वच्छ तकनीक का एकीकरण÷ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे इको-डिज़ाइन, अपशिष्ट पृथक्करण तकनीकें और हरित इंजीनियरिंग अपशिष्ट प्रबंधन को नया रूप दे सकती हैं।

प्रतिष्ठित अनुसंधान विद्वान प्रो. एम. पलानीवेल, (ग्रीनलिंक विश्लेषणात्मक और अनुसंधान प्रयोगशाला), डॉ. कलईसेलवी, (प्रोफेसर और प्रमुख (सेवानिवृत्त) पीएसजी सीएएस, कोयंबटूर), डॉ. जयंती (पेरियार विश्वविद्यालय), डॉ. दिनेश कुमार (विवेकानंद कला और विज्ञान महिला महाविद्यालय), और डॉ. एस. जयकुमार (एवीसी कॉलेज, मयिलादुथुराई) ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी सिद्धांतों और अपशिष्ट से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति से लेकर रीसाइक्लिंग नवाचारों और परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल तक के विषयों पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। उनकी भागीदारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार तमिलनाडु का क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान और अनुसंधान नवाचार राष्ट्रीय स्थिरता रणनीतियों में योगदान दे सकता है।

तमिल संसाधन व्यक्तियों की उपस्थिति से मध्य भारत के प्रतिभागियों को दक्षिण भारत के दृष्टिकोणों से जुड़ने का अवसर मिला, जिससे भाषाई, सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला। इस अंतर-सांस्कृतिक संवाद ने न केवल शैक्षणिक संबंधों को मजबूत किया, बल्कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की विविधता में एकता को भी प्रदर्शित किया।

डॉ. कलैसेल्वी, वरिष्ठ सलाहकार और परामर्शदाता, ग्रीनलिंक एनालिटिकल एंड रिसर्च लेबोरेटरी, जिन्होंने ÷क्लीनर टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स÷ पर बात की। उन्होंने पर्यावरण-दक्षता, कम कार्बन औद्योगिक पद्धतियों और प्रदूषण-निवारक दृष्टिकोणों की नींव के बारे में बताया। पेरियार विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. जयंती ने ÷अपशिष्ट से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति÷ पर बात की। उन्होंने भारत की ऊर्जा कमी के व्यावहारिक समाधान के रूप में बायोगैस संयंत्रों, अपशिष्ट-जनित ईंधन और अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण पर विस्तार से चर्चा की।

विवेकानंद महिला कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी के सहायक प्रोफेसर डॉ. दिनेश कुमार ने ÷रीसाइक्लिंग नवाचार और वृत्ताकार अर्थव्यवस्थाः समुद्री शैवाल अपशिष्ट पर केस स्टडीज़÷ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने समुद्री शैवाल आधारित जैव-उत्पादों, जैसे जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक, जैव-उर्वरक और अपशिष्ट जल अवशोषक, के आकर्षक उदाहरण साझा किए।

सेमिनार का समापन पैनल चर्चा के साथ हुआ, जिसमें सभी संसाधन व्यक्तियों के साथ-साथ दो छात्र प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस संवाद में अकादमिक शोध को नीति और उद्योग प्रथाओं में बदलने की व्यावहारिक रणनीतियों पर चर्चा की गई। छात्रों ने हरित रोज़गार, डिजिटल अपशिष्ट निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित अपशिष्ट विश्लेषण के बारे में प्रश्न पूछे। एक छात्र ने कहा, ÷इस सेमिनार ने हमें न केवल सिद्धांत सिखाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि हम भविष्य के पेशेवर के रूप में समाधान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।÷

कलिंगा विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय सेमिनार में प्रतिभागियों को वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, नीति निर्देश और व्यावहारिक नवाचार का समृद्ध मिश्रण प्रदान किया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुआयामी चुनौती है - जो जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, उद्योग और समाज तक फैली हुई है।

अपने समापन भाषण में, आयोजक और विज्ञान के डीन डॉ. आर. जयकुमार ने कार्यक्रम के सार को रेखांकित कियाः ÷हमारा लक्ष्य कचरे को संसाधनों में और चुनौतियों को अवसरों में बदलना है। यह सेमिनार दर्शाता है कि सहयोग और नवाचार के साथ, स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।÷ छात्रों को सलाह दी जाती है और उन्हें एक कागज़ का कप देकर कचरा प्रबंधन का अभ्यास कराया जाता है, उनसे कहा जाता है कि वे कप पर लिखें ÷मैं अपने कचरे के लिए ज़िम्मेदार हूँ÷ और हस्ताक्षर करें।

सेमिनार का समापन समापन सत्र, प्रमाण पत्र वितरण और प्रतिभागियों द्वारा अपने शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने और बढ़ावा देने की सामूहिक प्रतिज्ञा के साथ हुआ।

रायपुर : बलौदाबाजार जिले के किसान ऑयल पाम की खेती की ओर अग्रसर

ऑयल पाम की खेती की ओर अग्रसर

रायपुर, संवाददाता

भारत सरकार द्वारा तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल पाम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में किसानों को ऑयल पाम की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जिले के कृषकों में इस नई फसल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। अब तक विकासखंड सिमगा के ग्राम जरौद में 2 हेक्टेयर एवं भाटापारा के ग्राम बिजराडीह में 6 हेक्टेयर, कुल 8 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम पौधों का रोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

योजना के अंतर्गत कृषकों को सुविधाएँ योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रति हेक्टेयर 143 ऑयल पाम पौधों पर 29,000 रुपये की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। पौधों के रखरखाव, खाद-उर्वरक, थाला निर्माण आदि हेतु प्रथम वर्ष से चौथे वर्ष तक 5,250 रुपये प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 2,625 रुपये प्रति हेक्टेयर टॉप-अप सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। अंतरवर्ती फसल हेतु प्रथम से चौथे वर्ष तक अधिकतम 22,375 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

सिंचाई सुविधा हेतु न्यूनतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती करने वाले कृषक को एक बोरवेल हेतु 50,000 रुपये तथा प्रति हेक्टेयर अधिकतम 25,000 रुपये प्रति यूनिट की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार पम्पसेट हेतु 27,000 रुपये तथा प्रति हेक्टेयर 16,500 रुपये, फेंसिंग हेतु सीमेंट पोल एवं चौनलिंक पर 1,08,970 रुपये प्रति हेक्टेयर, तथा ड्रिप प्रतिस्थापन हेतु 14,130 रुपये प्रति हेक्टेयर के अतिरिक्त 8,635 रुपये टॉप-अप सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

युक्ति युक्तकरण से प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को मिली नियमित शिक्षिका

कोरबा

लम्बे समय से एकलशिक्षकीय की बाट जोह रहे पाली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम परसदा के प्राथमिक शाला लाइन पारा के विद्यार्थियों को नई शिक्षिका मिल गई है। पहले एकमात्र शिक्षका होने से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले विद्यार्थी अब नई मैडम के परमानेंट आ जाने से खुश है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशा निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण की प्रकिया अपनाई गई। युक्ति युक्तकरण की इस प्रक्रिया से जिले के सैकड़ों विद्यालयों के विद्यार्थियों को लाभ पहुचा है। खासकर शिक्षकविहीन और एकलशिक्षकीय वाले विद्यालयों में अतिशेष शिक्षको के समायोजन से शिक्षा की राह आसान हो गई है। जिले के अनेक दूरस्थ विद्यालय में युक्ति युक्तकरण से शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। ऐसे ही पाली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसदा के लाइनपारा में संचालित प्राथमिक शाला में 34 विद्यार्थी है। यहाँ प्रधानपाठक के रूप में श्री नोहर प्रसाद साहू है। उन्होंने बताया कि विद्यालय एकलशिक्षकीय था। युक्ति युक्तकरण से इस विद्यालय को एक नियमित शिक्षिका मिली है। शिक्षिका के आने से विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया हो गया है। युक्ति युक्तकरण से लाइन पारा के विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती नेमी जायसवाल का कहना है कि वह मूल रूप से पाली ब्लॉक के अन्य स्कूल में पदस्थ थी।

रायपुर : कमार दीदियों की ज़िंदगी में बिहान से जुड़कर आई खुशहाली

कमार दीदियों की ज़िंदगी

छः महीने में बाड़ी व्यवसाय से महिलाओं ने अर्जित की 25 हजार आमदनी

रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पीएम जनमन ग्राम बल्दाकछार की विशेष पिछडी जनजाति कमार महिलाओं ने बिहान समूह से जुड़कर अपनी आजीविका को नई दिशा दी है। बिहान योजना के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूह की 9 दीदियों ने सामूहिक रूप से बाड़ी और नर्सरी व्यवसाय की शुरुआत कर अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और खुशहाली का नया अध्याय लिखा है।

अप्रैल माह से आरंभ किए गए इस कार्य से महज छः महीनों के भीतर ही समूह ने सब्जियों की बिक्री से लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये तक की आमदनी अर्जित की है।

यह सफलता न केवल उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है बल्कि यह भी दर्शाता है कि संगठित होकर महिलाएं अपने आर्थिक भविष्य को मज़बूत कर सकती हैं। समूह की दीदियों ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा हुआ और आज वे अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों में आर्थिक योगदान दे रही हैं। वे कहती हैं– ÷प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा चलाई जा रही बिहान योजना ने हमारे जीवन को बदलने का अवसर दिया है। यह योजना हमारे लिए सिर्फ़ आत्मनिर्भरता का साधन नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।÷ आज बल्दाकछार की कमार दीदियां अपने परिश्रम और सफलता से न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। बिहान समूह के अंतर्गत किए जा रहे इस सामूहिक प्रयास से यह साबित होता है कि जब महिलाएं एकजुट होकर कार्य करती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान कर रही है।

ठाकुर कंप्यूटर एकेडमी, अंबागढ़ चौकी में शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन

राजनांदगांव।अंबागढ़ चौकी/

ठाकुर कंप्यूटर एकेडमी, अंबागढ़ चौकी में शिक्षक दिवस बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को सम्मानित कर आभार व्यक्त किया और विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सम्मानित शिक्षक श्री नीलकंठ कोमरे पधारे।

वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री देवकुमार यादव, श्री राजेश्वर साहू, श्री लेखराम ठाकुर, श्री विजय ठाकुर, श्री राजू निर्मल, श्री संता निषाद एवं श्रीमती भुनेश्वरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को गरिमामयी बनाया।

समारोह की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। स्वागत गीत की मधुर प्रस्तुति ने वातावरण को आनंदमय बना दिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान

विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत, नृत्य, कविताएँ एवं नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। शिक्षकों को सम्मान में पेन एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मेधावी विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम संचालन और संबोधन

समारोह का सफल मंच संचालन अरविन्द सिन्हा एवं यामनी लड़ेश्वर ने किया। अतिथियों का स्वागत करने के साथ-साथ समारोह को जीवंत बनाने में दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समारोह में मनहरण पिथौरा एवं देव यादव ने अपने प्रेरणादायी विचार रखे। उन्होंने शिक्षक दिवस के महत्व और गुरुजनों के योगदान पर प्रकाश डाला द्य

मुख्य अतिथि श्री नीलकंठ कोमरे ने कहा कि ÷शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और संस्कारों के भी निर्माता होते हैं। विद्यार्थी यदि गुरु का आदर करेंगे तो जीवन में सफलता निश्चित है।÷

खास खबर

13 साल के नाबालिग ने किया ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म

कोरबा,। कोरबा के सिविल लाईन थानाक्षेत्र में एक 13 साल के नाबालिग द्वारा अपने किरायेदार की ढाई साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़ित बच्ची की मां ने मकान मालिक ने बेटे को रंगे हाथों पकड़ा जिससे बाद मकान मालिक ने पीड़ित परिवार को ही घर से निकाल दिया है। शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को नाबालिग बालिक को हिरासत में लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार परिवार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। बच्ची के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते है वहीं मां भी प्राइवेट अस्पताल बिलिंग का काम में काम करती है। बुधवार को वह अपने काम से वापस घर लौटी। जब वह कमरे में गई, तो देखा कि मकान मालिक के बेटा बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा था। मां ने फ ैरन उसे पकड़ लिया और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जांच में यह भी सामने आया कि बच्चे से इसके पहले भी दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद मकान मालिक ने पीड़ित परिवार को धमकी देकर मकान खाली करने को कहा। ऐसे में परिवार को मजबूरन मकान छोड़ना पड़ा। मामले में पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मामले को बाल कल्याण समिति में पेश किया गया है।

पीजी कॉलेज के जनभागीदारी खाते से 6 लाख 7 हजार 980 रुपये की धोखाधड़ी

कोरबा, पीजी कॉलेज के जनभागीदारी खाते से 6 लाख 7 हजार 980 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी चेक का इस्तेमाल कर यह राशि निकाली है। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब राशि का आहरण होने के बाद पुलिस को शिकायत मिली। यह धोखाधड़ी सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, यह फर्जी चेक 11 से 19 अगस्त के बीच बैंक में जमा किया गया था। यह मामला तब सामने आया जब कालेज प्रबंधन को लेन-देन की जानकारी मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिली। जांच में यह भी सामने आया है कि पीजी कॉलेज का जनभागीदारी खाता एसबीआई में संचालित है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने संभवतः जाली हस्ताक्षर का उपयोग किया है, जो कॉलेज प्रबंधन के हस्ताक्षर से मिलता-जुलता है। यह भी माना जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति कॉलेज के खाते की जानकारी रखता था। यह अकेला मामला नहीं है। शहर में एसबीआई से फर्जी आहरण के कई और मामले भी सामने आए हैं, जिसमें मिनी माता शॉपिंग सेंटर के पास संचालित स्व सहायता समूह की महिलाओं के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हुआ था। इस मामले में भी 69 हजार रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है।

रायगढ़ मेरा परिवार, मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया बायंग एनीकट कम काजवे का भूमिपूजन, 38 करोड़ की लागत से सिंचाई और आवागमन सुविधा होगी बेहतर

100 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर संयंत्र और पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध होगी सिंचाई सुविधा

रायगढ़, । संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के ग्राम बायंग (कछार) में 38 करोड़ रुपये की लागत से मांड नदी बायंग एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इससे लाभान्वित गांवों में भू-जल संवर्द्धन होगा तथा आवागमन की सुविधा भी बढ़ेगी। एनीकट कम काजवे निर्माण से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर संयंत्र और पाइपलाइन के जरिए सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। झमुख्यमंत्री श्री साय ने लोकार्पण कार्यक्रम में ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि रायगढ़ क्षेत्र में जब भी मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही परिवार के बीच आया हूँ। आप सभी ने 20 वर्षों तक आशीर्वाद देकर मुझे सांसद बनाकर दिल्ली भेजा, अब मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने परिवार से मिलने आप सबके बीच आया हूँ। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विगत 20 महीनों में 'मोदी की गारंटी' के तहत अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इनमें धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता, तेंदूपत्ता संग्राहकों को पुनः चरण पादुका वितरण, किसानों को धान बोनस तथा 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रदेश के युवा देख रहे हैं कि जिन्होंने पीएससी परीक्षा में घोटालेबाजी की, वे जेल के अंदर हैं और कुछ जाने की तैयारी में हैं। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार में श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन योजना और बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा की योजना प्रारंभ की गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एनीकट भूमिपूजन के अवसर को बायंग (कछार) गांव के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था, उसे पूरा किया। अब गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, महतारी वंदन योजना का पैसा समय पर हर महीने मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन तथा डबल इंजन की सरकार में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं।

वित्त ओ.पी. चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रायगढ़ क्षेत्र का संसद में पिछले 20 वर्षों से प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे मुख्यमंत्री प्रत्येक गांव के लिए परिवार के सदस्य जैसे हैं। रायगढ़ से सांसद रहते हुए शायद ही ऐसा कोई गांव बचा हो जहाँ मुख्यमंत्री श्री साय न गए हों। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बने मात्र 20 महीने हुए हैं और इस अवधि में अनेक कार्य किए गए हैं। किसानों के एक-एकड़ पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, दो वर्षों का बकाया बोनस, भूमिहीन मजदूरों के खाते में हर साल 10 हजार रुपये की राशि पहुँच रही है।

हर गांव में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे हैं। राजमिस्त्री और सेंट्रिंग प्लेट कम पड़ गए हैं, फिर भी लगातार कार्य हो रहे हैं। केवल कछार गांव में ही 180 से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई गाथा लिख रहा है। हमारी माताएँ-बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

ग्राम पंचायत कछार के किसानों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एनीकट बनने से कृषि संबंधी सुविधाएँ बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि विष्णुदेव साय के सुशासन में सभी घोषणाएँ पूरी हो रही हैं और ऐसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति कर रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुजाता सुखलाल चौहान, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती गंगाबाई पटेल, ग्राम बायंग के सरपंच गौरीशंकर सिदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

हसदेव नदी संरक्षण के लिए होगा भव्य आरती का आयोजन

भाद्रपद पूर्णिमा पर माँ सर्वमंगला घाट में जुटेंगे पर्यावरण प्रेमी और समाजसेवी

कोरबा, लोकशक्ति।

कोरबा जिले की जीवनरेखा कही जाने वाली हसदेव नदी के संरक्षण और तट सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से कार्यरत नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को माँ सर्वमंगला घाट, कोरबा पर 'हसदेव आरती' का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि लोगों को नदी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का एक प्रेरणास्पद प्रयास भी है।

इसी श्रृंखला में आगामी 6 सितम्बर 2025 को भाद्रपद पूर्णिमा के पावन अवसर पर शाम 5 बजे भव्य हसदेव आरती का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्ति यजमान के रूप में उपस्थित रहेंगे, जो इस पवित्र मुहिम को और भी बल प्रदान करेंगे।

मुख्य यजमान के रूप में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री श्री राधेश्याम जायसवाल शामिल होंगे। वहीं, विशिष्ट यजमान के रूप में अनेक गणमान्य अतिथि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, जिनमें श्री हेमन्त माहुलीकर, प्रदेश महामंत्री, संस्कार भारती, छत्तीसगढ़, श्री नरेश कुमार अग्रवाल, प्रदेश सचिव, भारत विकास परिषद, छत्तीसगढ़, सुश्री जया मिश्रा, प्रदेश प्रभारी, महिला पतंजलि योग समिति, छत्तीसगढ़ और सुश्री ऋतु चैरसिया, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से शामिल हैं।

समिति का कहना है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हसदेव नदी और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने तथा जनमानस में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास है। नमामि हसदेव सेवा समिति ने कोरबा सहित आस-पास के सभी पर्यावरण प्रेमियों, युवाओं और श्रद्धालुजनों से अपील की है कि वे इस आयोजन में सपरिवार शामिल होकर न केवल पुण्य अर्जित करें, बल्कि एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के निर्माण में सहभागी भी बनें।

राजस्व कर्मियों की मिली-भगत : सरकारी जमीनों की जमकर हो रही बंदरबांट

कोरबा, संवाददाता। जिले में सरकारी जमीनों की जमकर बंदरबांट राजस्वकर्मियों की मिली भगत से हो रही है। जमीन के नक्शा,खसरा,रकबा और कई बार स्वरूप में तब्दीली करते हुए सरकारी जमीन को निजी बताकर तो वहीं सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा करने के साथ आंशिक निर्माण करते हुए उसे निजी जमीन की तरह बिक्री करने के मामले सामने आ रहे हैं।

सरकारी जमीन का निजी जमीन की तरह पट्टा भी प्रदान कर दिया जा रहा है और फिर वह जमीन बिक्री भी हो रही है। शासकीय योजनाओं के तहत जमीन प्राप्त कर लेने के बाद भी जमीन अपने पास न रखकर दूसरों को गैरकानूनी तरीके से बिक्री कर देने के भी मामले सामने आए। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है जिसमें पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के पटवारी हल्का लाद में पदस्थ पटवारी जितेंद्र कुमार भावे के द्वारा अपने कार्यकाल में सरकारी जमीनों का निजी नामांतरण करते हुए पट्टा जारी किया गया। यह मामला संज्ञान में आने के बाद सरकारी जमीनों को वापस शासन के खाते में मर्ज करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई तो रिकॉर्ड के अवलोकन के दौरान ज्ञात हुआ कि दो सरकारी जमीन बैंक में बंधक हैं। इन दोनों जमीनों के एवज में पट्टाधारक द्वारा केसीसी लोन ले लिया गया है। कोरबा जिले की सरकारी जमीन को निजी बनवाकर दुर्गा और बेमेतरा जिले के बैंक से दो अलग-अलग लोन उक्त जमीन को बंधक बनाकर प्राप्त कर लिया गया है। जांच आगे बढ़ी तो सारा मामला उजागर हुआ। बताया गया कि दोनों व्यक्ति दूसरे जिले से आकर यहां जालसाजी कर सरकारी जमीन हथिया लिये। नायब तहसीलदार की जांच को आगे बढ़ाते हुए एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर अजीत वसंत के समक्ष प्रस्तुत किया।

कटोही नाला उफनाया : गाडियों को कंधों का सहारा, बच्चों का स्कूल, आंगनबाड़ी जाना हुआ बंद

कोरबा,। बारिश के सतत सिलसिले ने शहर से लेकर ग्रामीणों क्षेत्रों में समस्याओं को बढ़ा दिया है। पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में कटोही नाला के उफनाने से कई क्षेत्रों के कनेक्टिविटी पर असर पड़ा। एक छोर से दूसरे छोर व आसपास तक जाने के रास्ते बंद हो गए। पानी उतरने पर गाडियों को लोगों के कंधों पर सवारी करानी पड़ी। लगातार हो रही बारिश की वजह से जटगा क्षेत्र का कटोही नाला पानी को बर्दाश्त नहीं कर सका। बड़ी मात्रा में बरसाती पानी आने से वह ओवरफ्लो हो गया। कई घंटे इसमें उफान की स्थिति रही। ग्राम पंचायत पचरा के आश्रित ग्राम अमाओहा में इस वजह से हालात विकट हो गए। बताया गया कि कटोही नाला जटगा से अमाओहा को जोड़ता है। मौजूदा स्थिति में यहां कई घंटे लोगों को समस्याओं से दो-चार होना पड़ा। भारी बारिश होने से जहां जनजीवन ठप हो गया वहीं अगली चुनौती नाला के उफनाने से पैदा हो गई। सडक संपर्क इस कारण से बाधित हुआ। जन सामान्य के साथ मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में लोगों के पसीने छूट गए। काफी इंतजार करने के बाद जब बारिश थमी और नाला का जल स्तर कम हुआ तो भी जोखिम कम नहीं हुई। ऐसे में चार-पांच लोगों के सहारे से दोपहिया गाडियों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने का काम हो सका, तब कहीं जाकर उनकी उपयोगिता साबित हो सकी। अमाओहा में लगभग 400 सौ से ज्यादा की जनसंख्या है। वहां एक आंगनवाड़ी प्राथमिक और मिडिल स्कूल संचालित हैं। जितने भी हाइ स्कूल में पढने वाले बच्चे जटगा जाते है और बरसात के दिनों बच्चें ही नई बल्कि शिक्षक लोग का आना जाना मुश्किल हो गया है। सूत्रों के अनुसार नाला में बनी समस्या से स्कूल और आंगनबाड़ी तक विद्यार्थियों की पहुंच मुश्किल भरी हो गई है।

इंडियन कॉफी हाउस में मनाया गया भव्य उत्सव

कोरबा, संवाददाता।

कोरबा अंचल के टी.पी. नगर स्थित इंडियन कॉफी हाउस में ओणम पर्व का आयोजन किया गया। यह पर्व दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता, और परंपरा का प्रतीक है। इस अवसर पर फूलों की रंगोली बनाई गई और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस उत्सव में उन्नीकृष्णन विनोद वैशाख, राजेश निगल, अरुन विष्णु जरीन और इंडियन कॉफी हाउस के समस्त कर्मचारियो ने भाग लिया। ओणम पर्व के अवसर पर लोगों ने नए कपड़े पहने, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और परंपरागत नृत्य और संगीत का आनंद लिया।

ओणम पर्व का महत्व

ओणम पर्व मलयाली कैलेंडर के अनुसार छिंगम महीने में मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त-सितंबर में पड़ता है। यह पर्व फसल कटाई के बाद मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा करना और फसल की समृद्धि के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना है।

ओणम पर्व की तैयारियाँ

ओणम पर्व की तैयारियाँ कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों को साफकरते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। घरों के आंगन में फूलों की रंगोली बनाई जाती है और घर के सदस्य नए कपड़े पहनकर त्यौहार का आनंद लेते हैं।

ओणम पर्व का सांस्कृतिक महत्व ओणम पर्व का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यह पर्व दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इस पर्व के दौरान लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करते हैं और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं।

ओणम पर्व कोरबा के टी.पी. नगर क्षेत्र में संचालित इंडियन कॉफी हाउस में धूमधाम से मनाया गया और यह पर्व दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बन गया।

सतरेंगा रिसोर्ट में पहुंचे जंगली भालू

कोरबा,)। सतरेंगा रिसोर्ट में गुरुवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक दो जंगली भालू गार्डन में घुस गए। जानकारी के अनुसार, रात करीब 11 बजे रिसोर्ट में बिजली गुल हो गई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर भालू सीधे रिसोर्ट परिसर में प्रवेश कर गए। घटना के दौरान वहां ठहरे पर्यटक और रिसोर्ट के कर्मचारी दहशत में आ गए और सुरक्षित जगहों पर भागकर छिप गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सतरेंगा क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से जंगली जानवर अक्सर आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन बिजली कटने पर अंधेरे का फायदा उठाकर भालू का रिसोर्ट परिसर तक आ जाना खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। करीब आधे घंटे तक भालू परिसर में घूमते रहे और उसके बाद जंगल की ओर लौट गए। इस दौरान गनीमत रही कि किसी भी पर्यटक या कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, इसलिए रिसोर्ट प्रबंधन को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष की तैयारी हुई तेज

संवाददाता

कोरबा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष (2025) की तैयारियों के अंतर्गत जिले के 612 ग्रामों में मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में विकासखंड कटघोरा के जवाली मंडल के 13 गाँवों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम में यह बैठक 1994 से लेकर अब तक 10वीं बार आयोजित हुई। बैठक का प्रारंभ खंड कार्यवाह श्याम सिंह द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत से किया गया। इसके बाद संघ की स्थापना, उद्देश्य और वर्तमान गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार और कुछ स्वयंसेवकों द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। स्थापना काल से ही संघ का ध्येय समाज का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र सर्वोपरि मानकर सेवा भाव से कार्य करना रहा है। खंड व्यवस्था प्रमुख लोकेश साहू ने जानकारी दी कि संघ वर्ष भर में छह प्रमुख पर्व मनाता है, जिसमे विजयादशमी पर्व, मकर संक्रांति एवं अन्य दान पर्व, हिंदू नववर्ष (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा), शिवाजी हिंदू साम्राज्य दिवस, गुरु पूर्णिमा (समर्पण दिवस), रक्षाबंधन पर्व आदि सम्मलित हैं। उन्होंने बताया कि शताब्दी पर्व के अंतर्गत इस वर्ष विजयादशमी (25 सितंबर से 15 अक्टूबर) विशेष रूप से मनाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक मंडल में पथ संचलन कर ग्रामवासियों तक संघ के विचार पहुंचाने की योजना है।

वर्तमान में देशभर में लगभग 6000 शाखाएँ सक्रिय हैं, वहीं कटघोरा खंड में 12 मंडल कार्यरत हैं, जिनमें प्रत्येक मंडल में 50 से अधिक स्वयंसेवक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।प्रांत प्रचारक अभयराम ने 3 सितंबर को अपने प्रवास के दौरान जय गर्ग निवास (गोपाल पेट्रोल पंप के सामने) में बताया कि संघ परिवार 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक घर-घर संपर्क अभियान चलाएगा, जिसे विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान माना जा रहा है। इसके अलावा 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक हिंदू सम्मेलन आयोजित होंगे, जिनमें पथ संचलन, सामाजिक सद्भाव बैठक, युवा कार्यक्रम और शाखा विस्तार प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे।

इसी क्रम में 5 सितंबर से ढेलवाडीह स्थित गुरुकुल विद्यालय में तीन दिवसीय प्रारंभिक वर्ग प्रशिक्षण का आयोजन भी होगा, जिसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के स्वयंसेवक शामिल होंगे। बैठक में 6 ग्रामो के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से शुक्रदास, ईश्वर प्रसाद बघेल, संजय कुमार, हर्ष चैहान, शिवरतन, अंजोर साय पटेल, गुलाब दास, हरीश कश्यप, वीरेंद्र नामदेव, महेंद्र कुमार यादव, वीरेंद्र पाल सिंह, श्रवण कुमार तंवर, दीपक पटेल सहित खंड कार्यवाह श्याम सिंह और खंड व्यवस्था प्रमुख लोकेश साहू शामिल थे। बैठक का समापन शांति पाठ के साथ किया गया।

कृषि विज्ञान केन्द्र बीजापुर के वैज्ञानिकों ने किसानों के खेतों में भ्रमण किया

बीजापुर। कृषि विज्ञान केन्द्र, बीजापुर के वैज्ञानिकों द्वारा जिले के किसानों के खेतों में भ्रमण किया गया। इस दौरान खेत में धान की फसल पर पत्ती मोड़क कीट (चितरी कीट) एवं केस वार्म कीट प्रकोप अधिकतर खेतों में देखा गया है। पत्ती मोड़क कीट (चितरी कीट) इल्ली अवस्था में फसल को नुकसान पहुंचाती है। पूर्ण विकसित इल्ली हरे रंग व 20-25 मि.मी. लम्बी होती है। यह कीट पत्तियों के दोनों किनारों को आपस में जोड़कर पत्तियों का हरा पदार्थ खुरजकर खा जाती हैं जिससे पत्तियों पर सफेद धारियां बन जाती है। केस वार्म कीट को बंकी कीट भी कहा जाता है इस कीट की इल्ली अवस्था फसल को नुकसान पहुंचाती है, पूर्ण विकसित इल्ली हरे रंग की व 15 से 20 मि.मी. लम्बी होती है। यह कीट पत्तियों को उपर से काटकर उसका खोल जैसा बना लेती है व इसके अन्दर रहते हुए पत्तियों पर चढ़कर हरा पदार्थ खुरजकर खाती है, जिससे पत्तियां उपर से कटी हुई व सफेद धारी युक्त दिखाई देती है। किसानों को पत्ती मोड़क एवं केस वार्म कीट के प्रबंधन के संबंध में जानकारी किसानों को दिया गया, इसे नष्ट करने हेतु इण्डोक्साकार्ब 15.80 प्रतिशत ई.सी. 200 मि.ली. प्रति हेक्टेयर या कार्टाप हाइड्रोक्लोराईड 50 डब्ल्यू. पी 1 किलो प्रति हेक्टेयर एवं केस वार्म नियंत्रण के लिए फेन्थोएट 50 प्रतिशत ई.सी. 500 मि.ली. प्रति हेक्टेयर या क्वॉनालफॉस 25 प्रतिशत को 2 मिली लीटर प्रति लीटर में छिड़काव के लिए निर्देश दिया गया। इसके साथ ही धान में नत्रजन पोषक तत्व की कमी के प्रबंधन के लिए नैनो यूरिया के प्रयोग 2-4 मिलीलीटर प्रति लीटर में छिड़काव एवं खरपतवार से होने वाली नुकसान और खरपतवार के प्रबंधन के बारे में जानकारी किसानों को दी गई। इसी प्रकार धान के आलावा भिन्डी, केला, और बरबट्टी फसलों के खेतों में भी भ्रमण किया गया। सब्जियों के फसल में लगाने वाले कीट एवं बीमारियों के संबंध एवं प्रबंधन के बारे में किसानों को जानकारी दिया गया। इसके साथ ही रबी मौसम में बोये जाने वाले फसलों बीज उपचार के लाभ के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान किया गया। सब्जी वर्गी फसलों में उचित जल निकास प्रबंधन के बारे में बताया गया।

जल संसाधन विभाग की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, टॉपर ने हासिल किए 83 अंक

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (ष्टत्र ङ्क4ड्डश्चड्डद्व) द्वारा आयोजित जल संसाधन विभाग की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 20 जुलाई को आयोजित की गई थी। परीक्षा में सिविल शाखा के टॉपर ने 100 में से 80.250 अंक, जबकि इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल शाखा के टॉपर ने 83 अंक प्राप्त किए हैं।

इस बार भी परीक्षा में कुछ सवालों को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं। तीन प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है, वहीं एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तरों को सही माना गया है। इससे पहले एडीईओ परीक्षा में भी व्यापमं ने 12 प्रश्न हटाए थे, जिसे लेकर परीक्षार्थियों ने असंतोष जताया था। जल संसाधन विभाग में सब इंजीनियर के कुल 121 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें सिविल ब्रांच के 105 पद और इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल के 16 पद शामिल हैं। सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में कुल 11,121 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जबकि इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल परीक्षा में 4,694 उम्मीदवारों ने भाग लिया। व्यापमं ने दोनों ही परीक्षाओं की प्राप्त अंकों के साथ संयुक्त मेरिट सूची (ष्टश्वद्बड्डद्बठ्ठद्गस्र स्द्गह्म्द्बह्ल स्द्बह्यह्ल) जारी कर दी है। परीक्षा परिणामों के साथ साथ संशोधित उत्तर कुंजी भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब अभ्यर्थी अपने अंकों की जांच कर सकते हैं।

पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले इवेंट मैनेजर समेत चार गिरफ्तार

रायपुर । राजधानी आयोजित होने वाली पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले इवेंट मैनेजर समेत चार आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी नाव्या मलिक सहित कुल 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 23.08.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत देवेन्द्र नगर ओव्हर ब्रीज के नीचे रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पास चारपहिया वाहन कार में सवार 03 आरोपी हर्ष आहूजा पिता अनिल आहूजा उम्र 23 साल निवासी कटोरा तालाब रतन पैलेस के पीछे आर्य समाज स्कूल के पास थाना सिविल लाईन रायपुर, मोनू विश्नोई पिता रामसिंग विश्नोई उम्र 29 साल निवासी ग्राम नंथला पोस्ट नंथला थाना अगरूवा मोड़ जिला हिसार हरियाणा तथा दीप धनोरिया पिता दिलीप धनोरिया उम्र 41 साल निवासी ए-401 समृद्धि फ्लैट अंवति विहार सेंट जेवियर स्कूल के पास खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ड्रग्स (एमडीएमए) कुल 27.58 ग्राम, घटना में प्रयुक्त सोनेट कार क्रमांक सी जी 04 क्यू जे 5466, नगदी रकम 85,300 रूपये एवं 05 नग मोबाईल जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 222/25 धारा 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

प्रकरण में एंड टू एंड कार्यवाही करते हुए प्रकरण के सभी बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेस पर टीम के सदस्यों द्वारा कार्य किया जा रहा था, इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा शहर में एमडीएमए का कार्टल संचालित करने वाली नाव्या मलिक तथा उसके साथी अयान परवेज के प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर टीम के सदस्यों द्वारा उनकी भी पतासाजी करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से प्रकरण से संबधित 03 नग मोबाईल फोन तथा 01 नग प्रतिबंधित नशीली दवाई जप्त की गई है। टीम के सदस्यों द्वारा गिरफ्तार आरोपी नाव्या मलिक एवं अयान परवेज से इस एम.डी.एम.ए कार्टल में संलिप्त आरोपियों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा माल को विधि अग्रवाल नामक महिला से प्राप्त करना बताने के साथ-साथ सोहेल खान तथा जुनैद अख्तर के भी प्रकरा में संलिप्त होना बताया गया। जिसपर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी सोहेल खान, जुनैद अख्तर एवं विधि अग्रवाल की भी पजासाजी कर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विधि अग्रवाल से प्रकरण में संलिप्त आरोपी एवं एमडीएमए उपलब्ध कराने वाले व्यक्यिों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा शंकर नगर निवासी श्र्श्री राज टण्डन के संबंध में जानकारी देने पर, प्रकरण में श्र्श्रीराज टण्डन को गिरफ्तार कर किया गया है। प्रकरण में संलिप्त गिरफ्तार आरोपियों का न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा प्राप्त कर बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेस के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संकल्प,समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़

महाराजा चक्रधर सिंह ने कला को दिलाई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान - मुख्यमंत्री श्री साय

रायगढ़ में चक्रधर समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का संकल्प - समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का संकल्प - समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ में चक्रधर समारोह के समापन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायगढ़ में कला और संस्कृति के प्रति अलग ही प्रेम है। इस प्रेम को स्थायी बनाए रखने की दिशा में यहाँ कला और संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा विगत वर्ष की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और महाविद्यालय हेतु स्थान का चयन भी हो चुका है। कुछ माह के पश्चात यह महाविद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने विगत 20 माह में अनेक योजनाएँ बनाई हैं और उन्हें जन-जन तक पहुँचाकर लोगों को लाभान्वित किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो गारंटी दी थी, उसे हमारी सरकार ने अल्प समय में ही पूरा किया है और 2047 तक के लिए छत्तीसगढ़ का विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना से लाभान्वित करते हुए हर माह उनके खाते में एक एक हजार रुपये की राशि डाली जा रही है। इससे राज्य की लगभग 70 लाख महिलाएँ लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति लागू कर राज्य में लाखों-करोड़ों रुपये का निवेश आकर्षित किया है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियों को रोजगार देने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में संस्कृति और आस्था की पहचान राजिम कुंभ को भी भव्य रूप देने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय सहित अन्य अतिथियों ने चक्रधर समारोह के समापन समारोह में आज के प्रमुख आकर्षण, प्रख्यात गायक पद्मश्री कैलाश खेर की प्रस्तुतियों का आम दर्शकों के साथ आनंद लिया।मुख्यमंत्री श्री साय और अन्य अतिथियों ने मंच से डाक विभाग द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह पर जारी विशेष आवरण का विमोचन किया। उन्होंने सुग्घर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर आधारित रायगढ़ नगर पालिक निगम के शुभंकर अप्पू राजा को भी लॉन्च किया। मंच पर कथक प्रस्तुत करने वाली विख्यात कलाकार पद्मश्री डॉ. नलिनी, डॉ. कमलिनी अस्ताना एवं उनकी टीम को सम्मानित भी किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान प्रारंभ से ही कला और संस्कृति की रही है। महाराजा चक्रधर सिंह ने यहाँ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने मंच से अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले सभी कलाकारों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं। चक्रधर समारोह के समापन अवसर पर उपस्थित हजारों की भीड़ को कला-प्रेमियों की पहचान बताते हुए स्थानीय विधायक एवं वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि रायगढ़ कला और संस्कृति की नगरी है। राजा चक्रधर सिंह ने कथक नृत्य और अन्य सांस्कृतिक विरासतों को आगे बढ़ाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हम सभी रायगढ़ के विकास को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने रायगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ और उससे होने वाली जॉब गारंटी का भी उल्लेख किया। साथ ही नालंदा परिसर की स्थापना के साथ आईआईटी, नीट, लॉ यूनिवर्सिटी सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश हेतु अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ के विकास में अनेक प्रोजेक्ट संचालित होने की जानकारी दी।इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह समारोह महाराजा चक्रधर सिंह के योगदान को समर्पित है। उन्होंने संगीत की खोती हुई विरासत को सहेजने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्य किया और संगीत के गौरव को पुनर्स्थापित किया।

कपड़ा दुकान में चोरी करने वाले दो नाबालिग सहित तीन गिरफ्तार

रायपुर,थाना देवेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत पण्डरी स्थित कपड़ा मार्केट की एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक वयस्क आरोपी सहित दो नाबालिग शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नगद राशि 25,000 भी बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी महेन्द्र पाल सिंह खुराना ने थाना देवेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान अमृत हाउस ऑफ कारीगरी (सुराना मार्केट, सिटी सेंटर मॉल के पीछे, पण्डरी रायपुर) से नगदी रकम चोरी हो गई है। दिनांक 23 अगस्त 2025 को रात्रि 9 बजे उन्होंने दुकान बंद की थी और 24 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे जब मैनेजर ने दुकान खोली, तो सारा सामान अस्त-व्यस्त मिला और कैश काउंटर का लॉक टूटा हुआ था। कैश काउंटर से रखी गई नगदी गायब थी। अज्ञात चोरों ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अपराध क्रमांक 172/25, धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा थाना देवेंद्र नगर की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आस-पास के लोगों से पूछताछ की गई। इसी दौरान एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तेलीबांधा निवासी आशीष यादव (उम्र 19 वर्ष) को हिरासत में लिया।

मुख्यमंत्री साय ने रायगढ़ जिले के ग्राम गढ़ उमरिया में नवगुरुकुल का किया शुभारंभ

रायगढ़ जिले के ग्राम गढ़ उमरिया में नवगुरुकुल का किया शुभारंभ

नवगुरुकुल : बालिकाओं की शिक्षा और संस्कारों के संवर्धन की नई पहल

रायपुर। बालिकाओं की शिक्षा और संस्कारों के संवर्धन की नई पहलमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के प्रवास के दौरान खरसिया तहसील अंतर्गत ग्राम गढ़ उमरिया में नवगुरुकुल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नवप्रवेशी छात्राओं को लैपटॉप वितरित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवगुरुकुल में स्थापित आधुनिक कंप्यूटर लैब का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे बालिकाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा और मूल्य आधारित संस्कार प्रदान करें ताकि उनका भविष्य सुनहरा बने। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम गणेशोत्सव, शिक्षक दिवस और चक्रधर समारोह की बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इसलिए समाज में उनका सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्मरण कराया कि पिछले वर्ष चक्रधर समारोह के समापन अवसर पर रायगढ़ में प्रयास विद्यालय का उद्घाटन किया गया था और आज नवगुरुकुल की स्थापना इस कड़ी को आगे बढ़ाती है। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, नवगुरुकुल की सह-संस्थापक सुश्री निधि और उनकी टीम की प्रशंसा की तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी बालिकाओं को बधाई देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार लगातार युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को व्यापक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से नवगुरुकुल संस्था द्वारा जशपुर जिले की 150 बालिकाओं को प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की सराहना की और इस प्रयास को और व्यापक बनाने की प्रेरणा दी।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था में प्रवेश पाने वाली 120 बालिकाएँ अपनी योग्यता और मेहनत का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास, ऊर्जा, जज्बा, जुनून और कठिन परिश्रम की पराकाष्ठा आवश्यक है। निराशा के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि निराशा के साथ कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। उप मुख्यमंत्री ने सभी बालिकाओं को निरंतर आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी।

ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले दो आरोपी

रायपुर। थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम लखौली स्थित एक ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चोरी की दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हुए दुकान से सोने-चांदी के जेवरात और नगदी चुरा लिए थे। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और दो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,50,000 बताई गई है। प्रार्थी राजेन्द्र सोनी ने थाना आरंग में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी ग्राम लखौली में स्थित ज्वेलर्स की दुकान में दिनांक 3 अगस्त 2025 की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रार्थी ने रात 8 बजे दुकान बंद कर ताला लगाया था, लेकिन अगली सुबह उसके बेटे ने सूचना दी कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि दुकान के शटर का ताला और कांच टूटा हुआ था तथा अंदर रखे सोने-चांदी के सभी जेवरात गायब थे। इस पर थाना आरंग में अपराध क्रमांक 441/25, धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नया रायपुर) विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट प्रभारी तथा थाना प्रभारी आरंग के मार्गदर्शन में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और मुखबिर सूचना के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर तिल्दा निवासी अजित जोगी देवार उर्फपोन्दी देवार (उम्र 21 वर्ष) और कुलदीप देवार (उम्र 19 वर्ष) को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने ज्वेलरी शॉप में चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने थाना पण्डरी और खरोरा क्षेत्र से चोरी की गई दो दोपहिया वाहनों का उपयोग किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात तथा घटना में प्रयुक्त दोनों चोरी की बाइक बरामद की, जिनकी कुल कीमत 1.5 लाख के आसपास है।

नई मैडम...नया सर.. युक्ति युक्तकरण से स्कूलों में पढ़ाई हुई बेहतर

किसान, महिलाओं और युवाओं की प्रगति ही राज्य का भविष्य

रजत जयंती वर्ष में 4000 पंचायतों में शुरू होंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र

खरसिया में किया रेलवे ओवरब्रिज सहित 66.84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन

श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और अटल परिसर का लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे ओवरब्रिज सहित 66.84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने 20 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा भी की। इनमें खरसिया के कबीर चौक से डभरा रोड तक बाईपास सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल सहित अन्य सुविधाओं की मरम्मत के लिए 2 करोड़ तथा खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये की घोषणा शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने खरसिया में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा अटल परिसर का लोकार्पण भी किया। साथ ही उन्होंने रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए तकनीकी सर्वे कराए जाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायगढ़ से उनका 20 वर्षों का पारिवारिक संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकायों में मिली जीत अटल विश्वास पत्र के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए सात से आठ हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अटल विश्वास पत्र में की गई एक-एक घोषणा को पूरा किया जा रहा है। मोदी जी की अधिकांश गारंटियाँ पूरी हो चुकी हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से खरीदी मूल्य 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मज़दूरों को प्रति वर्ष 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर भी अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग और शासकीय सेवाएँ गांव-गांव तक पहुँच रही हैं। 1460 पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, जहाँ न केवल पैसों का लेन-देन संभव है, बल्कि आय, भूमि, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ भी अब गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं।

फर्जी पुलिस बनकर केस सुलझाने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । रायपुर पुलिस ने बुधवार को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से पैसे लेकर केस सेटल करता था। आरोपी का नाम आशीष घोष है। उसे गुरुवार को अदालत में पेश करने के बाद 6 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।पुलिस ने आशीष के पास से 2 लाख रुपये नकद, सोने की दो अंगूठियाँ, दो सोने की चूड़ियाँ और अन्य कीमती सामान बरामद किया है, जिनका कोई वैध हिसाब आशीष नहीं दे सका। उसके मोबाइल की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई कई चैट्स में उसने पुलिस अफसरों को महंगे मोबाइल, बाइक और ब्रांडेड जूते गिफ्ट देने की बातें लिखी थीं। इतना ही नहीं, उसकी गाड़ी से एक थाने की नकली सील, ड्यूटी चार्ट और गश्त पॉइंट भी मिला है। मोबाइल फोन में कई अफसरों के साथ पार्टी करते हुए तस्वीरें और केस सेटलमेंट की बातचीत भी पाई गई। कई चैट डिलीट कर दी गई थीं, जिन्हें रिकवर करने के लिए मोबाइल को साइबर लैब भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आशीष छत्तीसगढ़ के कई थानों में बेरोकटोक आता-जाता था। वह थाने में दर्ज मामलों की जानकारी जुटाकर फरियादियों से संपर्क करता और बाहर बुलाकर पैसों के बदले मामलों को 'सुलझाने' का वादा करता था। उसने पुलिस अधिकारियों से करीबी रिश्ते बनाकर इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। पूछताछ में आशीष ने बताया कि वह एसीबी-ईओडब्ल्यू में तैनात एक सिपाही उमेश कुर्रे से मिला था। उसने उमेश के आईडी कार्ड की फोटो लेकर उसमें एडिटिंग की, अपनी तस्वीर लगाकर एक फर्जी पुलिस पहचान पत्र बनवाया। इस काम में उसे घड़ी चौक स्थित वीर नारायण परिसर की एक दुकान से मदद मिली। इस फर्जी ढ्ढष्ठ पर डीजी जीपी सिंह के नकली हस्ताक्षर भी मौजूद थे। आशीष सरगुजा का रहने वाला है और वहाँ के कई थानों के अधिकारियों से उसकी नजदीकी थी। वह न केवल थानों में जाता, बल्कि अफसरों के घरों तक पहुँचता और उनके परिवारों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करता था। इसके अलावा, वह एसीबी और ईओडब्ल्यू के कई अफसरों और कर्मचारियों के भी संपर्क में था।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)